राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 242 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार , 26 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

भारत ने दो दिन में ही जीता अहमदाबाद टेस्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने महज दो दिन में ही जीत हासिल कर ली। स्पिनर्स की मुफीद पिच पर भारत को महज 49 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल करने में उसे कोई दिक्तत नहीं आई। इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर सिमटने के बाद भारतीय टीम दूसरे दिन 145 रनों पर ढेर हो गई। भारत को पहली पारी में 33 रनों की बढ़त मिली। इसके बाद स्पिनर अक्षर पटेल व रविचंद्रन अश्विन ने दूसरी पारी में इंग्लैंड को 81 रनों पर समेट दिया। अक्षर ने 5 और अश्विन ने 4 विकेट लिये। टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर टेस्ट में 2-1 की बढ़त हासिल की। अश्विन ने इस टेस्ट में अपने 400 विकेट पूरे किए, वहीं विराट कोहली, घर में 22वीं जीत दर्ज कर महेंद्र सिंह धोनी 21 जीत के रिकार्ड को पछाड़कर सफल टेस्ट कप्तान बन गए हैं।

नीरव मोदी के खिलाफ भारत की बड़ी जीत

लंदन, (एजेंसी)। पंजाब नेशनल बैंक में अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटिश अदालत में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को हरी झंडी देते हुए कहा है कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वह दोषी साबित हो सकता है। 49 वर्षीय नीरव मोदी के दक्षिण-पश्चिम लंदन स्थित वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुआ। जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव का भारत में प्रत्यर्पण होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है।

सेंसेक्स 51 हजार के ऊपर बंद, निफ्टी में भी उछाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद घरेलू शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 257.62 अंक यानी 0.51 फीसदी की तेजी के साथ 51039.31 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 115.35 अंक यानी 0.77 फीसदी की तेजी के साथ 15097.35 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार सुबह 11.40 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों के चलते कारोबार बाधित हुआ था। एनएसई के वक्तव्य में कहा गया था कि नेट कनेक्टिविटी के लिए वह दो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेता है, लेकिन दोनों के एक साथ असफल होने से प्रणाली बाधित हुई है। इसके बाद दोपहर 3.45 बजे से बाजार में कारोबार शुरू हुआ व पांच बजे ट्रेडिंग बंद हुई।

बाइक बोट घोटाले में टीवी चैनल मालिक गिरफ्तार

लखनऊ, (एजेंसी)। बहुचर्चित बाइक बोट घोटाले में फरार चल रहे 50 हजार के इनामी अभियुक्त बीएन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने गुरुवार को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके से उसे गिरफ्तार किया। बीएन तिवारी लाइव टुडे न्यूज चैनल का मालिक भी है। लगभग 3500 करोड़ के इस घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू की मेरठ इकाई ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ से सहयोग मांगा था। बीएन तिवारी के लगातार फरार रहने से ईओडब्ल्यू ने गत एक फरवरी को लखनऊ में गोमती नगर थाना क्षेत्र स्थित तिवारी के घर आकर कुर्की की कार्रवाई की थी। इस दौरान घर का लाखों का सामान कुर्क करके थाना पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया था। तिवारी को भी इस घोटाले में अहम कड़ी माना जाता है, जिसने लखनऊ में बनाए गए संबंधों का लाभ इस ठग कंपनी को दिलवाया था।

ईडी ने दूसरे दिन श्रीनगर में लगातार छापे मारे

श्रीनगर, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी ने पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर आज उच्च सुरक्षा वाले इलाके शिवपोरा बटवारा छावनी क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता के पुत्र शमी सिंह ओबेरोय के घर में छापा मारा। उन्होंने बताया कि छापे मारने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पायी है। ईडी द्वारा बुधवार को टाटा मोटर्स के शोरूम में इसी तरह के छापे मारे गए।

मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय वाले बयान पर बरसे मोदी

प्रधानमंत्री बोले- झूठ के सहारे चलती है कांग्रेस

पीएम ने पुडुचेरी में की कई परियोजनाओं की शुरुआत

नई दिल्ली ■ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पुडुचेरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां कहा कि पुडुचेरी की हवा बदल रही है, जो इस सभा से दिखाई दे रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले चुनाव में पुडुचेरी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया। पीएम मोदी ने यहां राहुल गांधी के मछुआरों के लिए मंत्रालय वाले बयान पर भी पलटवार किया।पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों के सपनों को तोड़ दिया, यहां जो सरकार थी, वो लोगों की नहीं, बल्कि कांग्रेस हाईकमान की सेवा कर रही थी।

पीएम मोदी ने कहा कि यहां के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान की चप्पलें उठाते थे, लेकिन यहां के लोगों को गरीबी से नहीं निकाल पाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोगों के लिए काम नहीं किया, न ही कांग्रेस दूसरों को लोगों के लिए काम करने देती है। यहां की राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र की योजनाओं को यहां लागू नहीं होने दिया।

पीएम मोदी ने राहुल को घेरा

पीएम मोदी ने कहा कि दो दिन पहले एक महिला जब मुख्यमंत्री के बारे में शिकायत कर रही थी, पूरी दुनिया ने महिला की आवाज में उसका दर्द सुना, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने सच बताने की बजाय अपने ही नेता को गलत ट्रांसलेशन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यहां की कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनावों को नहीं कराया और वो लोग दूसरों को लोकतंत्र पर ज्ञान देते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी दौरे के दौरान मछुआरों से बात करते हुए कहा था कि वो केंद्र में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे। जिसके बाद केंद्र सरकार, भाजपा ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बांटो-झूठ बोलो और राज करो के हिसाब से काम करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पुडुचेरी दौरे के दौरान ही कई परियोजनाओं की शुरुआत की और हाइवे प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी।

डीएमके-कांग्रेस गठबंधन भ्रष्टाचार के हैकाथॉन जैसा

कोयंबटूर, (एजेंसी)। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) और कांग्रेस के बीच गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों विपक्षी दलों के बीच अंतर्विरोध इतना है कि वे तमिलनाडु में सुशासन नहीं दे सकते। डीएमके-कांग्रेस का गठबंधन भ्रष्टाचार के हैकाथॉन जैसा है। उन्होंने किसानों के कल्याण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हुए यह भी कहा कि वह बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता को खत्म कर उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद भाजपा की ओर से आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाना चाहती है। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान संगठनों द्वारा पिछले तीन महीने से अधिक समय से किये जा रहे आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह बयान काफी महत्व रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि सालों तक छोटे व्यवसायियों और छोटे किसानों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन एनडीए की सरकार ने इन दोनों वर्गों को शीर्ष प्राथमिकता में रखा। उन्होंने कहा कि भारत के छोटे किसानों के लिए काम करने का सम्मान मिलना हमारे लिए गर्व की बात है।

नेटफ्लिक्स-अमेजन से लेकर फेसबुक-ट्विटर के लिए बने सख्त कानून

नई दिल्ली, एजेंसियां। मोदी सरकार ने गुरुवार को इंटरनेट मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की। अब नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हों या फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबके लिए सख्त नियम बन गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। इसके अलावा कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर को भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण होगा और 15 दिनों में उसका निपटारा होगा। सरकार तीन महीने में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लागू करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों का व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेट मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का फोरम होना चाहिए। इसका दुरुपयोग रोकना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत में व्हाट्सएप के

53 करोड़, फेसबुक के 40 करोड़ से अधिक और ट्विटर पर एक करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। भारत में इनका काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसे लेकर काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने इसके लेकर गाइडलाइंस तैयारी की हैं। सोशल मीडिया के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होंगे।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सालों से इंटरनेट मीडिया पर बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। मंत्रालय ने व्यापक विचार-विमर्श किया और हमने दिसंबर 2018 में एक मसौदा तैयार किया। इसमें 2 श्रेणियां होंगी। एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी।

ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा। इसके अलावा कितनी शिकायतों पर कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट फैलाने वाले पहले इंसान की भी जानकारी देनी होगी। क्योंकि इसके बाद ही वह इंटरनेट मीडिया पर फैलता रहता है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशों से संबंध, दुष्कर्म जैसे अहम मामलों को शामिल किया जाएगा। यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।

इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा।

उम्र के अनुसार होगा सोशल मीडिया का वर्गीकरण

ओटीटी के लिए भी दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अश्लील सामग्री निरंकुश नहीं रह जाएगी। सरकार ने अभद्र कंटेंट पर अंकुश लगाने देश में कार्यरत सोशल मीडिया तथा ओटीटी कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सभी नियम आगामी तीन महीने में लागू हो जाएंगे। सोशल मीडिया और ओटीटी के लिए बनाए गए इस दिशा-निर्देश के मुताबिक हर कंपनी को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो 24 घंटे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों पर जवाब देगा और अनुपालन के लिए नियमित रिपोर्ट देंगे।

नए दिशा-निर्देशों के जरिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और समाचार से जुड़ी वेबसाइटों को नियमित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नए नियमों के तहत एक शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल बनाना होगा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें

- सभी को शिकायत निवारण की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए एक अधिकारी रखना होगा।
- अश्लील सामग्री मिलने पर 24 घंटे में हटाना होगा।
- सोशल मीडिया का वर्गीकरण दो प्रकार से होगा: पहला महत्वपूर्ण, दूसरा कम महत्वपूर्ण।
- मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी और स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।
- मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें बताना होगा कि कितनी शिकायतें आईं और कितनों पर काम हुआ
- सूचना का पहला स्रोत बताना ही होगा- जब खुराफात होती है तो ये बताना ही होगा कि सबसे पहले इसे किसने शुरू किया। अगर ये भारत के बाहर से हुआ है तो ये बताना होगा कि भारत में इसे सबसे पहले इसे किसने आगे बढ़ाया।
- महिलाओं से संबंधी अश्लील सामग्री दिखाने या प्रकाशित करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
- अगर आप प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं तो आपको किसी भी सामग्री को हटाने से पहले आपको यूजर को बताना पड़ेगा।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियमों और दायरे में ही काम करना होगा।
- बार-बार कहने के बाद भी ओटीटी वालों ने अपने लिए कोई नियमावली नहीं बनाई।

विस्फोटक भरी कार मिली अंबानी के घर के पास

मुंबई ■ एजेंसी

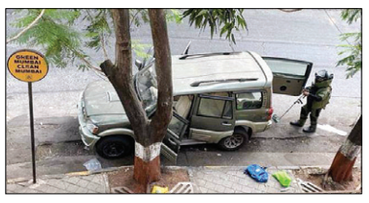

मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने से हड़कंप मच गया है। इसमें जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद हुई हैं। मौके पर मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची है और जांच में जुटी है। बम निरोधक दस्ते भी पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं।

जिलेटिन की 20 छड़ें भी बरामद, कमांडो तैनात

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है। उसमें जिलेटिन की छड़ पाई गई है। इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, जो भी असलियत है, जल्द से जल्द सामने आएगी।

मुंबई पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गामदेवी पुलिस स्टेशन के तहत एक संदिग्ध गाड़ी मिली है, जिसमें जिलेटिन की छड़ें हैं। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वायड और दूसरी पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं। गाड़ी की जांच में कुछ विस्फोटक सामग्री जिलेटिन मिली हैं। यह असेंबल्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं है। जांच जारी है।

पीएनबी घोटाले में लंदन की कोर्ट ने भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसियां। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले नीरव मोदी के तमाम बहानों को खारिज करते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने एक बहाना यह किया था कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह होना कोई अलग चीज नहीं है। नीरव मोदी का कोर्ट में कहना था कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्थर रोड जेल में आपको सभी जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी।

यही नहीं कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो उसके आत्महत्या करने का खतरा नहीं है। जज ने कहा कि नीरव मोदी को आर्थर रोड जेल में सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे और वह आत्महत्या जैसी स्थिति में न आए। इस तरह जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव का भारत में प्रत्यर्पण होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है।

नीरव मोदी ने अपने वकील के जरिए यह दावा भी किया कि भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केस को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन अदालत ने उसके सभी तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उनके केस को भारत में चलाने के लिए उनका प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए। हीरा कारोबारी नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है। अदालत के फैसले को इसके बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हालांकि, नीरव मोदी के पास अभी हाई कोर्ट में अपील का अधिकार है।

यही नहीं ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी को झटका देते हुए कहा कि उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है और गवाहों को भी धमकाने का प्रयास किया है।

विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह, बोलें- सिर्फ चुनावों में ही नजर आती है कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसियां । गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम दौरे पर हैं। गृहमंत्री ने यहां नगांव में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान (बोरडोवा सत्र) का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने नगांव के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया और पूजा भी की।

इस बीच गृहमंत्री ने असम को लेकर कहा कि हमें असम को बाढ़, घुसपैठियों और हिंसा से मुक्त करना है। साथ ही असम और पूरे उत्तर-पूर्व को जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र बनाना है। उन्होंने कहा, असम सरकार ने 180 करोड़ की लागत से इस स्थान को न केवल तीर्थ स्मरणीय स्मारक में बदलने का काम शुरू किया। बल्कि मुझे उम्मीद है कि ये स्थान विश्व और देशभर के धर्मप्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और यहीं से शंकरदेव का संदेश नई ऊर्जा के साथ पूरे देश में फैलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान पर असम सरकार ने 8,000 से ज़्यादा नाम घरों को (जो 50 साल से पुराने हैं) ढाई लाख रुपए देकर मज़बूत किया है।

इसके साथ ही भाजपा नेता अमित शाह ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह कहा कि असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, उसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग-अलग नाम से भाजपा के वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना लेकिन सबको मालूम है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। उन्होंने आने वाले दिनों में राज्य में होने वाले

विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, अब चुनाव आने वाला है और कांग्रेस की एक पद्धति है चुनाव आता है, तभी वो दिखाई देती है। इससे पहले वो दिल्ली की गलियों में घुमते और मौजमस्ती करते रहते हैं। उन्होंन कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व में विकास की नई शुरुआत हुई है। पहले असम आंदोलन, हिंसा से जाना जाता था, लेकिन आज मोदी जी ने असम का गौरव बढ़ाने के लिए ढेरों काम किए हैं।

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि असम में 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन कभी भी श्रीमंत शंकर देव जी की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उस पर एक स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने भाजपा को मौका दिया और हमारे दोनों नेताओं ने श्रीमंत शंकर देव जी के संदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्बी आंगलोंग में कहा कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन भूपेन हजारिका को किसी ने भारत रत्न नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारे संगीत को एक अलग मुकाम दिलाया है। आपकों बता दें कि इस साल आने वाले दिनों में जल्दी ही असम विधानसभा 2021 के चुनाव होने वाले हैं। यही कारण है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मी धीरे-धीरे तेज हो रही है।

यूपी में फिर से सख्ती; दूसरे राज्यों से आने वाले 14 दिन होंगे क्वारंटाइन

लखनऊ । महाराष्ट्र, केरल व मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में दोबारा कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के बाद यूपी भी अलर्ट हो गया है। यहां दोबारा कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए फिर से सख्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना को लेकर ढिलाई बिल्कुल भी न बरतने की हिदायत दी है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जैसे मार्च 2020 में संक्रमण फैलने पर बचाव के उपाय और सख्ती की जा रही थी, वैसे ही कठोर कदम फिर से उठाए जाएं। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को

14 दिन क्वारंटाइन करने के नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मोहल्ला व ग्राम निगरानी कमेटियों को फिर से अलर्ट कर दिया गया है। वह बाहर से आने वालों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देंगे। स्वास्थ्य विभाग पहले ही प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे मरीजों में से 10 फीसद के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला कर चुका है। नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सैंपल राजधानी स्थित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) भेजे जाएंगे। केजीएमयू की माइक्रोबॉयोलॉजी लैब इसके लिए तैयारी कर चुकी है। वहीं जरूरत पड़ने पर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बॉयोलॉजी (आइजीआइबी) को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ सख्ती भी बरती जाएगी।

टेस्टिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग पर फोकस- स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टेस्टिंग व कांटेक्ट ट्रेसिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है और अधिकतम 1.3 लाख टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में अब तक तीन करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट और 15.3 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

कोरोना संक्रमण के लगातार घटने के कारण प्रदेश में लेवल वन के अस्पताल बंद कर दिए गए थे। अब लेवल टू व लेवल थ्री के अस्पतालों में ही करीब 18 हजार बेड हैं। पहले सितंबर 2020 में सर्वाधिक 68,235 केस होने पर लेवल वन से लेकर लेवल थ्री तक के अस्पतालों में 1.5 लाख बेड की व्यवस्था की गई थी। हलांकि एक्टिव केस अब केवल 2190 हैं, लेकिन फिर भी जरूरत के अनुसार कोरोना के कम गंभीर मरीजों के लिए सीमित दायरे में लेवल वन की सुविधा शुरू होगी।

ताइवान में 228 Incident की बरसी पर मार्च, 1947 में 20 हजार लोगों का हुआ था नरसंहार

ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे में 228 घटना की 74 साल पूरा होने से पहले 200 से अधिक लोगों ने मार्च किया। 28 फरवरी, 1947 को ताइवान में लगभग 20,000 लोगों का नरसंहार हुआ था। ताइवान टाइम्स के अनुसार इसे लेकर लगातार पांचवी बार 21 फरवरी को रैली आयोजित हुई। त्सई जुई-यूहु डांस रिसर्च इंस्टीट्यूट और नायलॉन चेंग लिबर्टी फाउंडेशन एंड मेमोरियल म्यूजियम द्वारा पहली बार 2017 में यह रैली आयोजित की गई थी। रैली में हिस्सा लेने वाले समूहों में ताइवान एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स, कोवेनंट्स वॉच और 228 मेमोरियल फाउंडेशन शामिल थे।

अधिकांश प्रदर्शनकारियों ने काले रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने दातोंग जिले के रिक्सिन एलिमेंटरी स्कूल से अपना मार्च शुरू किया और तियानमा टी हाउस, टोबैको मोनोपॉली ब्यूरो की ताइपे शाखा और ताइवान ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से होते हुए एग्जिक्युटिव युआन तक गए। नायलॉन चेंग लिबर्टी फाउंडेशन एंड मेमोरियल म्यूजियम के निदेशक चेंग चू-मेई ने मार्च से पहले कहा कि अतीत को याद करने का उद्देश्य बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना है। 28 फरवरी, 1947 को तत्कालीन चीनी राष्ट्रवादी पार्टी शासन ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान ताइपे में गवर्नर-जनरल के कार्यालय (अब एग्जिक्युटिव युआन बिल्डिंग) में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने नागरिकों पर गोलियां चलाईं। इस दौरान प्रदर्शनकारी एक दिन पहले एक शख्स की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र में बोला भारत- पर्यावरण सुधार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2050 तक न बढ़े समय सीमा

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने कहा है कि पर्यावरण को लेकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2050 का समय निर्धारित नहीं होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से गंभीर प्रयास शुरू होने चाहिए और उन्हें जल्द प्राप्त किया जाना चाहिए। भारत की ओर से यह बात पर्यावरण, वन और मौसम से संबंधित मामलों के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पर्यावरण पर आयोजित चर्चा में कही।

जावड़ेकर ने कहा, विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे हर साल पर्यावरण सुधार के लिए वादे के अनुसार 100 अरब डॉलर (करीब 7.25 लाख करोड़ रुपये) की धनराशि दें। यह धनराशि पर्यावरण में सुधार के लिए विकासशील देशों में वितरित होने का प्रविधान है जिनमें भारत भी शामिल है।

जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण में सुधार के लिए प्रयास करने की घोषणाएं 2020 में की गई थीं। उनको पूरा करने के लिए 2050 का लक्ष्य निर्धारित करना उचित नहीं है। पर्यावरण में सुधार संबंधी उपायों के लिए आर्थिक, तकनीक और क्षमता बढ़ाने वाला समर्थन दिए जाने की जरूरत है। तभी कार्बन उत्सर्जन और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकेगा। पेरिस में हुए समझौते के मुताबिक 2050 तक दुनिया में कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा शून्य की जानी है। इसे 2030 तक आधी मात्रा में लाया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र का मौसम में बदलाव संबंधी 26 वां सम्मेलन नवंबर में ग्लास्गो में प्रस्तावित है। उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के कार्यक्रम में तेजी लाए जाने पर जोर दिया जाना है।

अमेरिका में बढ़ा भारतवंशियों का दबदबा, बाइडन ने किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन में किया नामित

वाशिंगटन। अमेरिका की नई सरकार में भारतवंशियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय-अमेरिकी वकील और अधिकार कार्यकर्ता किरण आहुजा को कार्मिक प्रबंधन के कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। कार्मिक प्रबंधन, एक संघीय एजेंसी है जो अमेरिका के 20 लाख से अधिक सिविल सेवकों का प्रबंधन करती है। अगर सीनेट द्वारा इस फैसले पर मुहर लग जाती है तो 49 वर्षीय किरण आहूजा अमेरिकी सरकार में इस शीर्ष स्थान पर सेवा करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी बन जाएंगी।

किरण आहूजा ने साल 2015 से 2017 तक अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के स्टाफ के प्रमुख के रूप में काम किया है। उनके पास दो दशकों से अधिक सार्वजनिक सेवा और गैर-लाभकारी/परोपकारी क्षेत्र के नेतृत्व का अनुभव है। किरण आहूजा वर्तमान में परोपकारी संस्थानों के एक क्षेत्रीय नेटवर्क परोपकार नॉर्थवेस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग में एक नागरिक अधिकार वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया, स्कूल के अलगाव के मामलों को सुलझाया और विभाग के पहले छात्र नस्लीय उत्पीड़न मामले को दायर किया। 2003 से 2008 तक किरण आहूजा ने राष्ट्रीय एशियाई प्रशांत अमेरिकी महिला मंच, एक वकालत और सदस्यता संगठन के संस्थापक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।

नस्लवाद पर पूर्व यूएस प्रेसिडेंट का खुलासा

ओबामा बोले- एक दोस्त ने रंगभेदी कमेंट किया था, मैंने उसकी नाक तोड़ दी थी

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने साथ हुए नस्लभेद पर रोचक घटना बताई। ओबामा के मुताबिक- स्कूल के दिनों में मेरे एक साथी ने मुझ पर नस्लभेदी और रंगभेदी टिप्पणी की थी, गुस्से में मैंने उसकी नाक तोड़ दी थी। ओबामा के अनुसार, यह घटना स्कूल के लॉकर रूम में हुई थी। ओबामा 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए। उस दौरान जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और अब वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं।

ओबामा के अनुसार, यह घटना स्कूल के लॉकर रूम में हुई थी। ओबामा 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए।

पोडकास्ट में शामिल हुए ओबामा

'द हिल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नस्लभेद पर ओबामा ने यह खुलासा एक पॉडकास्ट के दौरान किया। इस प्रोग्राम के एंकर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे। ओबामा ने इस घटना के बारे में कहा- मैं जब स्कूल में था तो मेरे कई दोस्त थे। एक दोस्त खास था। हम साथ में बास्केटबॉल खेलते थे। एक बार हम खेल रहे थे और इसी दौरान आपस में झगड़ा हो गया। उसने मुझसे कुछ नस्लभेदी शब्द कहे। उसने शायद जो कुछ कहा, उसका अर्थ भी वो नहीं जानता था। मैं गुस्से में था। मैंने एक घूंसा उसकी नाक पर मारा और उसकी नाक तोड़ दी। इस पर एंकर ने कहा- आपने बिल्कुल सही किया।

फिर मतलब समझाया

अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे ओबामा ने आगे कहा- घटना के बाद मैंने अपने उस दोस्त को बताया कि उसने जो कहा उसका क्या मतलब होता है। माना जा रहा है कि ओबामा ने पहली बार इस तरह की घटना का सार्वजनिक तौर पर जिक्र किया है। ओबामा के मुताबिक, मैं गरीब और बदसूरत हो सकता हूं, लेकिन इसके यह मायने बिल्कुल नहीं हैं कि कोई मेरा अपमान करे। और जो गलती मैंने नहीं की, उसकी सजा कैसे मिल सकती है.

पहले भी यह मुद्दा उठा चुके हैं ओबामा

अमेरिका में पिछले चुनाव में नस्लवाद का मुद्दा कई बार उठा। ओबामा ने अपने कार्यकाल और इसके बाद भी कई बार इस मुद्दे का जिक्र किया है। 2015 में उन्होंने कहा था- अमेरिका में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है। हम इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यह 300 पहले हो सकता था, लेकिन अब तो इसकी कोई जगह हो ही नहीं सकती।

पाक सांसद का नाबालिग से निकाह: 62 साल के पाकिस्तानी सांसद ने 14 साल की बच्ची से शादी की, अब पुलिस जांच करेगी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के बलूचिस्तान से सांसद मौलाना सलाहउद्दीन अयूबी (62) ने 14 साल की बच्ची से शादी कर ली। मामला कुछ वक्त पुराना है। पहले भी चर्चा में आया था, लेकिन तब इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। अब एक NGO की अपील पर पुलिस इसकी जांच करने जा रही है। बच्ची के पिता ने भी निकाह की पुष्टि की है।

पाकिस्तान में निकाह कानून की बात करें तो यहां लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल तय है। अगर इससे कम उम्र में शादी की जाती है तो कानूनी तौर पर यह गुनाह माना जाएगा और इसके लिए सजा भी हो सकती है। मौलान अयूबी बलूचिस्तान के चित्राल से सांसद हैं। उन्होंने कभी इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वे मौलाना फजल-उर-रहमान की पार्टी से सांसद हैं। रहमान इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता हैं। यह फ्रंट इमरान सरकार के खिलाफ देश में आंदोलन चला रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के स्कूल ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट मीडिया को जारी किया है।

इसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 2006 बताई गई है। इसके बाद एक लोकल हलह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इसकी जांच की जाएगी। मौलाना के निकाह का मामला पिछले साल का है।

तब लोकल मीडिया में इस तरह की खबरें आई थीं, हालांकि पुष्टि इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि मौलाना अयूबी या लड़की के परिवार ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था।

सच्चाई छिपाने की कोशिश: चीन में तीन ब्लॉगर समेत 7 लोग गिरफ्तार, इन पर गलवान में मारे गए सैनिकों की बेइज्जती का आरोप

बीजिंग। बीजिंगचीन ने गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों के अपमान के आरोप तीन ब्लॉगर समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक, चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। करीब 8 महीने बाद आधिकारिक तौर पर उसने सिर्फ चार सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है।

सरकार से सवाल नहीं कर सकते

'इकोनॉमिक ऑब्जर्वर' अखबार के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्यू जिमिंग भी गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। उन्हें नानजिंग प्रांत से गिरफ्तार किया गया। क्यू ने सोशल मीडिया पर मारे गए चीनी सैनिकों की सही संख्या जाननी चाही थी। उन्होंने कहा था कि जो सैनिक मारे गए हैं और जो कमांडर गंभीर रूप से घायल है, उनकी भी सही पहचान

बताई जानी चाहिए। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीवो पर क्यू के 25 लाख फॉलोअर हैं। चीन में ट्विटर की जगह माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बीवो ही है।

सरकार ने आठ महीने सच क्यों छिपाया

क्यू ने सोशल मीडिया पर सरकार के इरादों पर सवालिया निशान लगाए। पूछा- सरकार यह बताए कि जब भारत ने अपने सैनिकों के शहीद होने की बात घटना के फौरन बाद स्वीकार कर ली थी तो हमारी सरकार ने 8 महीने क्यों लगाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने कम नुकसान झेलकर बड़ा फायदा हासिल कर लिया हो। क्यू की गिरफ्तारी पर पुलिस ने कहा- वे सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, क्यू ने अपने ऊपर लगे आरोप कबूल कर लिए हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया है।

और लोगों पर भी सख्ती

वीचैट पर इसी मामले का जिक्र करने वाले 28 साल के एक और ब्लॉगर को भी अरेस्ट किया गया है। इसका सरनेम चेन बताया गया है। आरोप है कि इस ब्लॉगर ने भी भारत की घुसपैठ और चीनी सैनिकों के मारे जाने पर भ्रामक जानकारी शेयर की थी। इसके अलावा एक और ब्लॉगर को सिचुआन प्रांत से गिरफ्तार किया गया है। बाकी चार लोगों के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं दी गई।

पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करो: पेरिस में FATF के हेडक्वॉर्टर के सामने इमरान सरकार और फौज के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन

लंदन। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग जारी है। गुरुवार या शुक्रवार को पाकिस्तान पर बड़ा फैसला आ सकता है। आतंकवाद को पनाह और फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान करीब दो साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है। पेरिस में जारी मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच, हजारों लोगों ने पेरिस में FATF के हेडक्वॉर्टर के सामने इमरान खान सरकार और फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने की मांग की।

दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकी पालता है

पेरिस में पाकिस्तान के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में पत्रकार, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और उईगर समुदाय के लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने साफ कहा- पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज और वहां वर्तमान इमरान खान सरकार खुलेआम दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है।

वहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। आतंकी संगठनों के लिए पैसा जुटाया जा रहा है। इसके बावजूद अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी।

जवाबदेही तय की जाए

पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ताहा सिद्दीकी ने कहा- हम यहां इसलिए जुटे हैं ताकि ख्रज्ञख्र के सदस्य देशों को यह बताया जा सके कि वे चीन के दबाव में न आएं और बिना वक्त गंवाए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करें। पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया को खतरनाक बना रहे हैं। पाकिस्तान खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन करता है और उन्हें फंड देता है। अब वक्त आ गया है जब दुनिया पाकिस्तान और चीन के इस नापाक गठजोड़ के खिलाफ बेहद सख्ती से कदम उठाए।

आतंकी रिहा किए जा रहे हैं

पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की मीटिंग जारी है। गुरुवार या शुक्रवार को पाकिस्तान पर बड़ा फैसला आ सकता है। आतंकवाद को पनाह और फंडिंग के आरोप में पाकिस्तान करीब दो साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है। पेरिस में जारी मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।

पश्तून मूवमेंट से जुड़े फजल रहमान अफरीदी ने कहा- अगर दुनिया को महफूज बनाना है तो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर लगाम कसनी होगी। वहां पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। इसके गुनहगार आतंकी उमर शेख को रिहा कर दिया जाता है। ओसामा बिन लादेन यहां मिलता है। हर बड़ा आतंकी इसी मुल्क में पनाह लेता है। अब दुनिया को और क्या सबूत चाहिए। वहां की अदालतें भी आतंकियों के हक में फैसले सुना रही हैं। उमर शेख को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही रिहा किया।

दुबई : कोरोना केस बढ़ते ही सभी बार और पार्टियां बंद, एयरपोर्ट पर अब चेहरा ही होगा पासपोर्ट

अबू धाबी। यूं तो दुनिया के 2 बड़े इवेंट गल्फ फूड और डिफेंस एक्सपो दुबई और अबू धाबी में चल रहे हैं और बिलियन डॉलर के सौदे भी हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की वापसी ने यहां सबकी चिंता बढ़ा दी है। रोज औसतन 2800 संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना की इस लहर में मौतों की संख्या में भी उछाल देखने को मिल रहा है। 19 फरवरी को कोरोना से 20 मौतें दर्ज की गई हैं।

हालांकि 97.7 लाख की आबादी वाले यूएई में 55.6 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सरकार टेक्नोलॉजी और सख्ती से कोरोना का मुकाबला कर रही है। सरकारी दफ्तरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रोबोट की मदद से काम हो रहा है। दुबई इमीग्रेशन पर आईआरआईएस टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। इसमें मुसाफिर का चेहरा ही उसका पासपोर्ट है। दुबई ने सख्ती करते हुए सभी पब और बार को बंद कर दिया है। रेस्टोरेंट्स भी इवेंट्स या पार्टी नहीं कर सकते हैं। बढ़ती सख्ती का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि दुबई ने कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर जनवरी में 14 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किया था और 213 पर जुर्माना लगाया था। वहीं, बीते एक हफ्ते में 31 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।

इसमें नियम तोड़ने पर एक डेजर्ट टूरिस्ट कैंप, याट पार्टी और प्राइवेट पार्टी पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वॉट्सएप पर कोरोना पीसीआर टेस्ट का ऑफर देने वाली एक ट्रेवल एजेंसी को भी सील कर दिया है। सिनेमा हॉल और इनडोर इवेंट की कैपसिटी को 50त्न कर दी है। अबू धाबी में भी पार्टी पूरी तरह से बैन है।

सिनेमा हॉल भी बंद हैं। शादी में 10 और शोक सभा में 20 लोगों की ही इजाजत कर दी गई है। जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें हर हफ्ते पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिसंबर में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल और न्यू ईयर में लाखों यात्री आए। इस दौरान की गई लापरवाही ने कोरोना को वापसी में मदद की है।

कोरोना दुनिया में: यूरोपीय यूनियन के 6 देश बॉर्डर बैन खत्म करने पर राजी, ब्रिटिश पीएम बोले- जून तक हालात सामान्य हो जाएंगे

लंदन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.26 करोड़ से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 95 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

EU का फैसला

ईयू यानी यूरोपीय यूनियन के 6 देश बॉर्डर पर आवाजाही सामान्य करने पर राजी हो गए हैं। यह प्रतिबंध अब तक दो बार लगाए और फिर हटाए जा चुके हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने यह फैसला किया है। इस बारे में यूरोपीयन कमीशन को एक रिपोर्ट भेजी गई है। इस पर आज फैसला हो सकता है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम जारी रहेंगे। हाल के दिनों में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच इस मुद्दे पर तनाव हो गया था। इसके बाद हालात सामान्य करने पर सहमति बनी।

जून तक हालात सामान्य होने की उम्मीद

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देश में लगे तमाम तरह के प्रतिबंधन जून तक हटा लिए जाएंगे और हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। एक प्रोग्राम के दौरान जॉनसन ने कहा- सरकार अपनी तरफ से हर वो

कदम उठा रही है, जो हालात सामान्य कर सकते हैं। हम पहले ही आर्थिक स्थिति सामान्य करने के लिए पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। जॉनसन ने फिर कहा है कि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्लान बनाया जा चुका है और इस पर अमल किया जा रहा है। इसमें एक्सपर्ट्स की राय को भी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल भी बहुत जल्द खोल दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं।

फ्रांस में दिक्कत बढ़ी

फ्रांस के अस्पतालों में मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। IC में भर्ती मरीज काफी तेजी से बढ़े हैं। 12 हफ्ते में पहली बार आंकड़ा 3 हजार से ज्यादा हुआ।

कुल 3 हजार 435 मरीज IC में एडमिट किए गए। इनमें से कुछ की हालत तो काफी गंभीर बताई गई है। फ्रांस के हालात इसलिए भी चिंताजनक माने जा सकते हैं क्योंकि यूरोप के बाकी देश बॉर्डर प्रतिबंध खत्म करने पर विचार कर रहे हैं और आज इस पर फैसला भी हो सकता है, लेकिन फ्रांस सरकार किसी मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती।

उसने लॉकडाउन से तो इंकार किया है, लेकिन बाकी प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला किया है।

इटली पर गंभीर आरोप

'द गार्डियन' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इटली ने पिछले साल फरवरी में WHO को महामारी के बारे में सही जानकारी नहीं दी, जबकि देश में केस मिलने शुरू हो गए थे। दरअसल, दुनिया के तमाम देशों को इंटरनेशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स का पालन करना होता है।

साल की शुरुआत में बीमारियों से जुड़ी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देनी होती है। इटली ने 4 फरवरी 2020 को यह रिपोर्ट तो दी, लेकिन इसमें खुद को लेवल 5 पर बताया। इसके मायने ये हैं कि किसी बीमारी से लड़ने की उसकी तैयारी सही स्तर पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक इटली ने 2006 के बाद राष्ट्रीय महामारी उन्मूलन यानी महामारी से निपटने का प्लान ही अपडेट नहीं किया। दावा किया जाता है कि अमेरिका से पहले इटली में महामारी ने दस्तक दी। चीन के बाद इटली पहला देश था, जहां महामारी पैर पसार चुकी थी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कार्यो की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा, अप्रैल में खोलने की तैयारी

दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कार्यो की बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। एनएचएआइ (नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया) के सचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस बैठक में हिस्सा लेते हुए अब तक हुए कार्यो का विवरण पेश किया।

एनएचएआइ के अफसरों ने बताया कि प्रोजेक्ट के कार्यो को लेकर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। इस प्रोजेक्ट में आ रहीं अड़चनों को दूर कर दिया गया है। बैठक में संकेत मिले हैं कि इस एक्सप्रेस-वे को वाहनों के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में खोल दिया जाएगा। एनएचएआइ के अफसरों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में समय लगेगा। एनएचएआइ ने इसको पूरा करने के लिए दिसंबर तक की मोहलत मांगी, जो मिल गई है। आरओबी निर्माण कार्य के साथ इस एक्सप्रेस-वे को तकनीकी तौर पर वाहनों के लिए खोला जा सकता है। बैठक में रेलवे के अफसरों ने चिपियाना आरओबी एवं डासना आरओबी के लंबित डिजायन को मंजूरी दे दी है। चिपियाना आरओबी के लिए गार्डर डालने के लिए रेलवे ट्रैक को ब्लाक करने की मंजूरी शेष रह गई है।

एनएचएआइ द्वारा प्रस्तावित तिथियों के अनुसार रेलवे ने ब्लाक के लिए सहमति देने का वादा कर दिया है। 82 किलोमीटर लंबे और छह लेन चौड़े इस एक्सप्रेस-वे की कुल लागत 4,974 करोड़ रुपये है। दो चरणों का काम पूरा होने के बाद वाहन दौड़ रहे हैं तो दो चरणों का काम अंतिम चरण में हैं। प्रोजेक्ट का मुख्य रूप से केवल तीन स्थानों पर काम बचा हुआ है। चिपियाना आरओबी का काम बचा हुआ है। डासना आरओबी के गार्डर डल चुके हैं। एलिवेटेड रोड इसी आरओबी पर टिका है। महरौली में तीन सौ मीटर लंबी सड़क निर्माण का काम अवशेष है जो एक महीने में बन जाएगी।

फरवरी में 3 बार बढ़े रसोई गैस के दाम

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के लोगों को महंगाई का एक ओर झटका लगा है। दिल्ली में एक बार फिर रसोई गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, यह इजाफा सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि देशभर में हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इजाफा किए जाने के बाद बृहस्पतिवार से राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 794 रुपये हो गया है। इसमें 25 रुपये का इजाफा किया गया है। इससे पहले यह 769 रुपये था। बृहस्पतिवार को जब लोग रसोई गैस की बुकिंग कराने लगे तो उन्हें बढ़े दाम के बारे में जानकारी मिली। फरवरी महीने में अब तक तीन बार रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फरवरी महीने में

14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों तीसरी बार इजाफा किया है। इसके पहले IOCL ने 4 फरवरी और 14 फरवरी को दाम बढ़ाए गए थे। इस तरह रसोई सिलेंडर के दामों 1 IOCL ने 4 फरवरी को रसोई गैस के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 15 फरवरी को सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए। 25 फरवरी को IOCL ने 25 रुपये की बढ़ोतरी की। बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा हुआ था। एक दिसंबर को ढ्ढह्लष्टरु ने 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 594 रुपये से बढ़ाकर 644 किया गया ?था। इसके बाद 15 दिसंबर को इसकी कीमत में इजाफा करते हुए 694 रुपये कर दी थी। इसके बाद जनवरी में तो कीतम में इजाफा नहीं किया, लेकिन फिर फरवरी में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर में तीन बार इजाफा हो चुका है। बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 694 रुपये थी। शुक्रवार को जहां ढ्ढह्लष्टरु ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है तो सरकारी तेल विपणन कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की कई है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल 90.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 81.32 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

एक लाख के इनामी लक्खा सिंह का दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज आ रहा हूं दिल्ली

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर हरियाणा-दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर चल रहा पंजाब और हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 92वें दिन पहुंच गया। इस बीच 26 जनवरी को लालकिला उपद्रव मामले में एक लाख के इनामी पंजाबी गैंगस्टर लक्खा सिंह सिधाना ने दिल्ली पुलिस को फिर से चुनौती दी है। इंटरनेट मीडिया पर फिर एक वीडियो अपलोड कर लक्खा सिंह सिधाना ने कहा है कि बठिंडा में उसकी रैली सफल हो गई और अब दिल्ली में रैली करनी है। उधर, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लाल किला हिंसा के आरोपित पंजाबी एक्टर दीप सिंधु के फेसबुक पर फिर एक वीडियो अपलोड कर सात किसान नेताओं पर उपद्रव कराने का आरोप लगाया गया है।

कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों द्वारा 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी लक्खा सिंह सिधाना पर एक लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। इतना ही नहीं, लक्खा सिधाना लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपित भी है।

गौरतलब है कि 23 फरवरी को पंजाब के बठिंडा में आयोजित किसान महारैली में पहुंचे दिल्ली हिंसा के आरोपित लक्खा सिधाना ने पुलिस को चकमा दिया और फरार भी हो गया। बठिंडा के गांव महराज में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस मौजूद थी, बावजूद इसके लक्खा सिंह सिधाना मंच से फरार होने में सफल हो गया। बता दें कि दिल्ली हिंसा के आरोपित सिधाना पर एक लाख का इनाम घोषित है और 26 जनवरी से फरार है और लगातार वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस के साथ-साथ पंजाब पुलिस को भी चुनौती दे रहा है।

यहां पर बता दें कि महराज गांव सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी पैतृक गांव है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर लक्खा सिंह सिधाना ने पंजाब के किसानों से अपील की थी कि वे किसान आंदोलन की बागडोर दोबारा अपने हाथ में लें। इसके अलावा उसने पंजाब के किसानों से 23 फरवरी को बठिंडा के गांव महराज में आयोजित रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही थी। ऐसा हुआ भी, इस रैली में लोग आए थे।

कृषि उन्नति मेले में बोले नरेंद्र तोमर- टैक्स माफ करने वाली सरकार का विरोध करना क्या न्यायोचित है

नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर पूसा में बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय कृषि विज्ञान मेले की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। आत्मनिर्भर किसान की थीम पर आधारित तीन दिवसीय मेले में इस बार कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों को उपज मंडी से बाहर किसी को भी और कहीं भी बेचने की आजादी देता है। नया कृषि कानून कहता है कि न तो राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार बिक्री पर टैक्स लगा सकती है। आप ही बताएं टैक्स हटाने वाली सरकार अच्छी है या टैक्स लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले ऐसे लोग हैं जो

उनका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने टैक्स माफ किया है। आप ही बताएं क्या ये न्यायोचित है। उन्होंने कहा कि कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का योगदान आजादी के बाद जीडीपी में बढ़ा लेकिन कृषि का नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि क्षेत्र में तमाम तरह की बंदिशें थी। निजी निवेश यहां नहीं होता था। यह क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित रहा। लेकिन हमलोगों ने कृषि क्षेत्र पर अन्य क्षेत्रों के समान ही ध्यान देना शुरू किया। किसानों की तकलीफों को समझा। जो कानूनी बंदिशें थी, उसे हटाया। पहले किसान खाद बीज के लिए साहूकार की ओर देखता था लेकिन अब ऐसा नही है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लाई गई। जब हम लोग सत्ता में आये थे तब इस मद में 6.5 लाख करोड़ कर्ज दिया जाता था अब इस बजट में 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। लोकतंत्र में कोई भी सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत नहीं कर सकती है। वहीं, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि देश भले ही 1947 में आजाद हुआ लेकिन किसान सही मायने में कृषि कानून आने के बाद 2020 में आजाद हुआ। हमें कृषि कानून को अच्छे से समझने की जरूरत है। अभी तक देश में किसानों को बेचारा समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक कहानियों में भी कहा जाता था कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और एक शहर में धनाढ्य व्यक्ति रहता था। इस धारणा को बदलने की जरूरत है। किसान गरीब नहीं रहेगा। इस बार मेले में किसानों को पूसा संस्थान द्वारा विकसित नई किस्मों की सजीव प्रदर्शनी देखने को मिलेंगी। इसमें दलहन, तिलहन के अलावा बागवानी से जुड़ी किस्में शामिल हैं। विज्ञानियों ने सजीव प्रदर्शन के लिए कई महीने पूर्व ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। किसानों को प्रदर्शनी के दौरान यदि कुछ जानने की जरूरत होगी तो फार्म पर मौजूद विज्ञानी उनके एक- एक सवाल का जवाब उन्हें देंगे।

दिल्ली में मार्च-अप्रैल महीने में हो सकती है पानी की किल्लत

नई दिल्ली। मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। इस बीच दिल्ली के लाखों लोगों के लिए बुरी खबर आ रही है। इससे मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत रहेगी। इस बाबत दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले महीने 25 मार्च से 24 अप्रैल के बीच ब्यास नदी से एक माह के लिए पानी आपूर्ति रोकने जा रही है। इससे दिल्ली 232 एमजीडी पानी की आपूर्ति कम हो जाएगी। ऐसे में दिल्ली में 25 फीसद पेयजल की कमी हो जाएगी। नांगल हाइडल चैनल के प्रस्तावित मरम्मत कार्य के लिए पानी रोकने की जानकारी दी गई है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली का पानी नहीं रोकने की केंद्र सरकार से मांग की है।

दिल्ली के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, कोरोना का नहीं लिया टीका तो होगा भारी नुकसान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर चलाए जा रहे टीकाकरण को स्वैच्छिक करार दिया है। लेकिन, पूर्वी निगम के शिक्षा विभाग के अधिकारी इसे जबरन कराने की तैयारी में हैं। शाहदरा उत्तरी जोन के सहायक शिक्षा निदेशक ने तो इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिया। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी अपनी बारी अपने पर टीका नहीं लगवाते हैं तो बाद में कोविड के कारण किसी तरह की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्वयं की है। निगम की तरफ से कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा। इसे लेकर नगर निगम के शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।

बुधवार को शाहदरा उत्तरी जोन के सहायक शिक्षा निदेशक कामलेश्वर शाह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है। लेकिन, कई लोग टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। यदि भविष्य में कोविड के कारण कोई परेशानी या दुर्घटना होती है तो ऐसे लोगों को लाभांश से वंचित कर दिया जाएगा।

इससे पहले शाहदरा दक्षिणी जोन के सहायक शिक्षा निदेशक अनिल बालियान ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों के वाट्सएप ग्रुप पर टीका लगाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले शनिवार को एक बैठक में उपायुक्त ने सौ फीसद टीकाकरण लक्ष्य दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी टीका नहीं लगाएंगे, उनके बारे में जानकारी प्रधानाचार्य देंगे। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों आदेश पर शिक्षक यूनियन ने नाराजगी जाहिर की है। नगर निगम शिक्षक संघ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष विभा सिंह का कहना है कि टीकाकरण स्वैच्छिक है। प्रधानाचार्य अपने कर्मचारियों को इसे लगाने की सलाह तो दे सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा समय में कोरोना होने पर निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहां तक कि बीमारी के दौरान अर्जित अवकाश ही काटा जाता है। ऐसे में इस प्रकार की चेतावनी कहीं से भी जायज नहीं है। इस संबंध में शाहदरा उत्तरी जोन के उपायुक्त राजशेखर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की।

निहंग सिखों का एलान, दिल्ली के सभी 90 रास्ते किए जाएंगे बंद; नहीं होने देंगे दूध व सब्जियों की आपूर्ति

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कानूनों की मांग को लेकर दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर चल रहा किसाना का धरना-प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 92वें दिन पहुंच गया। सिंघु के साथ टीकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। इस बीच किसान संगठनों ने बृहस्पतिवार को देश की राजधानी दिल्ली में दूध व सब्जी आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है। बाहरी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर जुटे प्रदर्शनकारी निहंग सिखों ने एलान किया है कि अभी तो दिल्ली के चार रास्तों को ही बंद किया गया है। आने वाले दिनों में अब अन्य सभी रास्ते भी बंद किए जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली में दूध और सब्जी की आपूर्ति भी रोक दी जाएगी। किसान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली के सभी 90 रास्ते बंद किए जाएंगे। निहंग सिखों ने मंच से यह

केंद्र सरकार के साथ दोबारा बातचीत शुरू नहीं होने से ज्यादातर किसान प्रदर्शनकारी निराश है। इसके साथ ही दबी जुबान से किसान संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

एलान किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि धरना-प्रदर्शन की आगे की कड़ी में दिल्ली में दूध व सब्जियों की आपूर्ति नहीं होने दी जाएगी। यहां पर बता दें कि पश्चिमी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बेहद कम रह गई है। पिछले कुछ दिनों से काफी कम संख्या में प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के साथ दोबारा बातचीत शुरू नहीं होने से ज्यादातर किसान प्रदर्शनकारी निराश है। इसके साथ ही दबी जुबान से किसान संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों कहा है कि वे अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवा लें, जल्द ही 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। हमें जमीन बचाने को सरकार से लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने किसानों के साथ पुलिसकर्मियों की भी चिंता की। भाकियू नेता टिकैत ने बुधवार को आगरा के किरावली में किसान महापंचायत को किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून के नाम पर व्यापारियों को लाभ नहीं देने दिया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे भी आंदोलन का हिस्सा बनें।

प्रदर्शन की वजह से 90 दिन से परेशान हो रहे आम लोग, भीड़ दिखाने को खड़े हैं ट्रैक्टर

बाहरी दिल्ली। सिंघु बार्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को बुधवार को 90 दिन हो गए। इन 90 दिनों में स्थानीय लोगों व राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो कई दिल्ली छोड़कर अपने घर चले गए हैं। पिछले वर्ष 27 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया था। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसके दो दिनों के बाद 29 नवंबर को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) का जत्था गांवों के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर गया था और सिंघु बार्डर-नरेला रोड पर पहुंच गया था। उन्होंने यहां पर मंच लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। तब से राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर दो मंचों का संचालन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के नेता इन दिनों सिंघु बार्डर पर भीड़ जुटाने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जब भीड़ नहीं जुट रही तो भीड़ दिखाने के लिए सड़कों पर खाली ट्रैक्टर खड़े कराए जा रहे हैं। बहरहाल, धरना

स्थल के पंडाल तो खाली ही नजर आ रहे हैं। करीब 24 दिन के बाद सिंघु बार्डर पर दिल्ली की सीमा में पंजाब से एक सौ से ज्यादा ट्रैक्टर ट्राली तो आ गए हैं, लेकिन धरना स्थल पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। कुछ कृषि कानून विरोधी अगर धरना स्थल पर बैठते भी हैं तो कुछ समय बाद उठकर टेंट व ट्राली में चले जाते हैं। दरअसल जब से किसानों ने सीमाओं पर धरना देकर प्रदर्शन करना शुरू किया है उसके बाद से ही ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। आम लोगों को अपने वाहन के साथ आने जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलना पड़ रहा है उसके बाद भी वो परेशान हो रहे हैं। जाम की वजह से रास्ते में घंटे लग जाते हैं।

कृषि कानून वापस न लिए जाने पर राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापस न लिए जाने पर अब एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब संसद मार्च करना होगा। इसी के साथ इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च किया जाएगा।

इन दिनों वो देश के अलग-अलग राज्यों में जाकर वहां किसानों की महापंचायत कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में रैली के दौरान राकेश टिकैत ने ये नया ऐलान किया है। दरअसल इससे पहले 26 जनवरी को भी किसानों के संगठन की ओर से ट्रैक्टर रैली निकालने का आवाहन किया गया था। उस रैली की आड़ में राजधानी की सड़कों पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था, इसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

उपद्रवियों ने लालकिले की प्राचीर पर चढ़कर वहां झंडा फहराया था, इसके अलावा लालकिले पर उस जगह भी झंडा फहराया था जहां से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडारोहण करके राष्ट्र को संबोधित करते हैं। किसानों के इस उपद्रव की पूरे विश्व में आलोचना हुई थी। अब राकेश टिकैत ने फिर से इससे बड़ी रैली निकालने की घोषणा करके एक बार फिर उस दिन को याद दिला दिया है। राजस्थान में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की एक नजर खेत पर रहनी चाहिए दूसरी नजर दिल्ली में आंदोलन पर और तीसरी नजर संयुक्त किसान मोर्चे पर। सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है इसलिए आने वाले समय में संसद के पास पार्क में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाना पड़ेगा। संसदीय समिति बनाएं और वहां कुछ फसलों की खेती करवाएं। जो लाभ-हानि हो उसे समिति देखे और उस आधार पर फसलों के दाम तय करें। उधर दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी और टिकरी बॉर्डर पर लगाये गए नोटिस के बाद किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की कार्रवाई बताते हुए कड़ा विरोध जताया है।

इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉ. दर्शनपाल ने बयान जारी करते हुए इन कार्रवाई को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से किसान आंदोलन कमजोर होने के बजाय मजबूत होता जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा के डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आये भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बजाय किसानों को ही गिरफ्तार कर लिया। सरकार के किसान विरोधी साजिशों का हम कड़ा विरोध करते है। भाजपा द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की रोज कोशिशें की जा रही है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे और किसानों का यह संघर्ष जरूर कामयाब होगा।

हुनर हाट में देश भर के दस्तकारों और शिल्पकारों की दिख रही प्रतिभा

दक्षिणी दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहे हुनर हाट में देश भर के दस्तकार और शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षामंत्री के उद्बोधन को साकार रूप देते हुए शिल्पकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कालीन हों, या बारामुला से आने वाले फ्लोर मेट। लकड़ी की दस्तकारी और जूट के बने हुए उत्पाद लोगों को खूब भा रहे हैं। जूट उद्योग न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि महिला सशक्तीकरण का उत्कृष्ट नमूना भी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपने जूट के बने उत्पाद लेकर दिल्ली के हुनर हाट में आई सोमश्री दास गुप्ता बताती हैं कि उनके इन उत्पादों से एक हजार से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनके उत्पाद न केवल इको फ्रेंडली हैं, बल्कि इनसे महिलाओं का सशक्तीकरण भी हो रहा है। उनके पास हैंड बैग, घरेलू सजावट के सामान, डोर मेट व फ्लोर मेट से लेकर घरेलू उपयोग की वस्तुओं की बड़ी रेंज है। उनके पास 50 से 10 हजार रुपये तक की कीमत के सामान उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं को बनाने में घरों से निकले हुए जूट का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे महिलाएं एकत्र करती हैं और उन्हें नए स्वरूप में ढाल देती हैं।

राजस्थान से आए यूसुफ हाथों से बनाई गई रजाई लेकर आए हैं, जिसका पूरा काम घर में ही किया गया है। यह मौसम के हिसाब से गरमाहट देती है। उप्र के रामपुर गांव से आए नौशाद अहमद बताते हैं कि कोराई ग्रास मेट है, जो तमिलनाडु में होने वाली कोरा ग्रास से बनी है। इसे साफ भी कर सकते हैं, वहीं गुजरात के कच्छ जिले को पहचान कच्छ एंब्रायडरी है। यह हैंडवर्क है। एक-एक धागा हाथ से बुना हुआ है। सूती या रेशमी कपड़े पर तैयार की गई कच्छ वर्क कढ़ाई के पैटर्न बनाने के लिए महीन टांके के लिए रेशम या ऊनी धागे का इस्तेमाल किया जाता है।

तब्लीगी मरकज का ताला खुलवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। आलमी तबलीगी मरकज निजामुद्दीन का ताला खुलवाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका पर न्यायमूर्ति गुप्ता की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वक्फ बोर्ड ने अधिवक्ता रमेश गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में मरकज प्रकरण में जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए जांच रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने की मांग की है। याचिका में दलील दी गई है कि वक्फ अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को संचालित करने की संवैधानिक शक्ति वक्फ के पास है और पुलिस प्रसाशन द्वारा तालाबंदी करना वक्फ की शक्तियों में दखल देना है। सुनवाई के दौरान केंद्र

सरकार की तरफ से मौजूद रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह संवेदनशील और अहम मामला है और इसमें केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि इस मामले में कई मामले विचाराधीन है और इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन धार्मिक प्रतिष्ठान को लम्बे समय तक बंद रखना गैरजरूरी है। याचिका में कहा गया कि इस संबंध में फरवरी 2021 को दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित करने के बाद कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तब्लीगी मरकज निजामुद्दीन पर पुलिस-प्रशासन ने तालाबंदी कर दी थी और यह अब तक जारी है। बता दें कि तबलीगी मरकज निजामुद्दीन के मुखिया मौलाना साद समेत कई लोगों के खिलाफ कोरोना महामारी के दौरान नियमों की अवहेलना के मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। आरोप है कि देश-विदेश से मरकज में आए लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया जिससे दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ा। इस मामले में तब्लीगी जमात से जुड़े कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी। कई लोगों पर बिमारी को फैलाने का आरोप भी लगा था।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कार्यो की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा, अप्रैल में खोलने की तैयारी

दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कार्यो की बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। एनएचएआइ (नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया) के सचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस बैठक में हिस्सा लेते हुए अब तक हुए कार्यो का विवरण पेश किया। एनएचएआइ के अफसरों ने बताया कि प्रोजेक्ट के कार्यो को लेकर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। इस प्रोजेक्ट में आ रहीं अड़चनों को दूर कर दिया गया है। बैठक में संकेत मिले हैं कि इस एक्सप्रेस-वे को वाहनों के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में खोल दिया जाएगा। एनएचएआइ के अफसरों ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि चिपियाना रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में समय लगेगा। एनएचएआइ ने इसको पूरा करने के लिए दिसंबर तक की मोहलत मांगी, जो मिल गई है।

संपादकीय

बोलने की आजादी के आर्थिक हित

चुनाव हारने के बाद से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या-क्या खोया है? दो चीजें तो जगजाहिर हैं- राष्ट्रपति पद, और दुनिया का सबसे प्रभावशाली पोस्टल एड्रेस, यानी ह्वाइट हाउस। लेकिन चुनाव हारने के बाद इन चीजों को तो उन्हें खोना ही था। एक चीज, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा है, वह है ट्रंप का ट्विटर अकाउंट, जो पिछले महीने की 6 तारीख की कैपिटल हिल की घटना के बाद उनसे छीन लिया गया था। इसका डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने से उतना लेना-देना नहीं है, जितना कि उनकी हरकतों से है। मीडिया की दुनिया में खबरों के बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन पिछले चार साल में उनका ट्विटर अकाउंट खबरों का जितना बड़ा स्रोत रहा, उतना शायद कोई दूसरा नहीं रहा। पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव अभियान चलाने के बाद से अकाउंट पर पाबंदी लगने तक डोनाल्ड ट्रंप ने 34,000 से ज्यादा ट्वीट किए। यानी वह हर रोज औसतन 20 से 25 ट्वीट करते रहे। उनके ये ट्वीट अपने उस कट्टर समर्थक वर्ग से जुड़ने के औजार भी थे, जिसे खुद उन्होंने तैयार किया था। और ऐसे ही औजारों के जरिए उन्होंने इस वर्ग को अमेरिकी संसद पर हमले के लिए भी उकसाया था। इस पर विवाद बढ़ने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया था।

हालांकि, जब उनके अकाउंट को बंद किया गया, तब भी वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह बात अलग है कि तब तक वह चुनाव हार चुके थे। वैसे ट्विटर ने उनके इस अकाउंट को चुनाव नतीजों से पहले ही अविश्वसनीय बना दिया था। उसने उनके ट्वीट पर विवादास्पद या भ्रामक का लेबल लगाना शुरू कर दिया था। इससे कुछ और पहले, कोरोना संक्रमण के समय ट्विटर ने उनके कई ट्वीट पर यह लिखा था कि ट्वीट में दिए गए तथ्य सही नहीं भी हो सकते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन आज इनको एक बार फिर तब याद करना जरूरी है, जब भारत में कुछ अकाउंट को लेकर भारत सरकार और ट्विटर आपस में उलझे हुए हैं। किसान आंदोलन और 26 जनवरी को दिल्ली व लाल किले की घटनाओं के बाद सरकार ने ट्विटर से बहुत सारे अकाउंट व हैशटैग बंद करने के लिए कहा था। ट्विटर ने उन्हें शुरू में बंद भी किया, पर बाद में ज्यादातर को बहाल कर दिया। सरकार की तरफ से जब सख्ती दिखाई गई, तो ट्विटर ने एक ब्लॉग लिखा, जिसमें यह सोशल मीडिया मंच अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के चैंपियन की तरह दिखाई देता है। हमारे सामने ट्विटर के दो रूप हैं। अमेरिका में वह नफरत को रोकने की कोशिश में वहां के राष्ट्रपति तक से भिड़ने की मुद्रा में दिखाई देता है, और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार के दबाव का विरोध करता प्रतीत होता है। वैसे एक तीसरा रूप भी है। बाकी तमाम सोशल मीडिया मंचों की तरह ही ट्विटर का भंडार भी नफरत फैलाने वाली सामग्रियों से भरा पड़ा है। वहां जितनी अच्छी बातें हैं, उतनी ही नफरत वाली भी होंगी, या शायद उनसे ज्यादा भी हों। जिस तरह से यह माना जाता है कि पैकेजिंग उद्योग के आने के बाद समाज में कूड़े की मात्रा बढ़ गई है, वैसे ही एक धारणा यह भी है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से सामाजिक परिदृश्य में नफरत भी बढ़ गई है। यह भी कहा जाता है कि ऊपरी तौर पर सोशल मीडिया की सभी कंपनियां नफरत की बातों को खत्म करने के संकल्प लेती दिखाई देती हैं, पर यह नफरत ही घुमा-फिराकर उनके लिए मुनाफे का सौदा भी होती है। उसके खिलाफ वे तभी सक्रिय होती हैं, जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है।

सरकारें अभिव्यक्ति की या दूसरी तरह की आजादी पर हल्ला बोलती हैं, जो कोई नई बात नहीं है। यह जरूर है कि इन दिनों इंटरनेट पर पाबंदी जैसा एक नया आयाम इनमें जुड़ गया है, अन्यथा इसमें कुछ भी नया नहीं है। पिछले कुछ दिनों से रूस में जो हो रहा है और पिछले कुछ समय में हांगकांग और युगांडा वगैरह में जो हुआ है। म्यांमार की घटना तो बिल्कुल ताजा है। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि नागरिक आजादी पर पाबंदी का काम अब सरकारें नए ढंग से करने लगी हैं। अब वे सीधे उस माध्यम को रोकती हैं, जिनके जरिए लोग आपस में संवाद करते हैं। लेकिन यह पाबंदी काफी महंगी भी पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ खबरों, अभिव्यक्ति और संवाद-संपर्क का जरिया नहीं, बल्कि व्यापार और कारोबार का भी माध्यम है। लोगों को लंबे समय तक चुप कराए रखने की बात तो सोची जा सकती है, लेकिन एक हद के बाद उद्योग-व्यापार को रोकना संभव नहीं होता। इसी पूरे दौर में एक नई चीज जरूर हुई है।

सोशल मीडिया चलाने वाली कुछ कंपनियां हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करती दिखाई देती हैं। पिछले कुछ समय में दुनिया में एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा हुआ है, जिसके कारोबारी हित हमारी अभिव्यक्ति की आजादी से चाहे-अनचाहे जुड़ गए हैं। इसके साथ ही यह वही बिजनेस मॉडल है, जिसके हित सनसनी में भी हैं और शायद काफी हद तक नफरत में भी। खबरों में भी हैं और फेक न्यूज में भी। इसमें किसी को अंतर्विरोध भी दिख सकता है और विडंबना भी, हकीकत भी यही है। ये ऐसी कंपनियां हैं, जिन्हें हर देश की सरकार किसी-न-किसी तरह से नियंत्रित करने की फिराक में रहती है, लेकिन वे किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं हैं। इसलिए उन्हें पूरी तरह से बंद कर पाना भी संभव नहीं है और शायद इसीलिए कई बार हम उनसे बड़ी उम्मीद भी बांध पाते हैं। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन अक्सर बहुत सी अच्छी चीजें अंतर्विरोधों के बीच ही खड़ी रह पाती हैं। सरकारें भी इस बात को जितनी अच्छी तरह समझ लें, उनका इसी में भला है।

प्रवीण कुमार सिंह

हुनरमंदों के लिए विदेश में अवसर, जापान ने खोले भारतीय श्रमिकों के लिए द्वार

> भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों को लेकर हुए समझौते के अतिरिक्त अब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के कुशल कामगारों को अपने यहां रोजगार देने में रूचि दिखाई है।
>
> विश्व के तकनीकी दिग्गज देश भी भारतीय मजदूरों की कुशलता का लोहा मान रहे हैं। भारत सरकार के साथ इन देशों द्वारा किए जाने वाले समझौतों से यह स्पष्ट हो रहा है। इससे हमारे श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर तो बनेंगे ही, साथ ही एक निश्चित अवधि के बाद जब ये श्रमिक वापस आएंगे तो अपने साथ नई तकनीकों से संबंधित अनुभव भी लाएंगे जिसका उपयोग यहां किया जा सकता है।

कोरोना का टीका आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटने लगी है। परंतु अर्थव्यवस्था को पहले की तरह पटरी पर तेजी से दौड़ने से जुड़ी एक चिंता कायम है, वह है रोजगार। आंकड़े बता रहे हैं कि जितनी तेजी से जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पुराने स्तर की ओर अग्रसर है, उतनी तेजी रोजगार के अवसर सृजन करने में नहीं दिख रही है। बजट पूर्व चर्चाओं में लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने इस विषय को लेकर चिंता जाहिर की थी और अब जब बजट सामने है तो यह कहना गलत नहीं होगा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न सिर्फ इस चिंता को समझा, बल्कि जितना संभव था इस मामले के व्यावहारिक समाधान पर जोर दिया। वस्त्र उद्योग और मत्स्य उत्पादन जैसे श्रम गहन क्षेत्रों को लेकर जिन कदमों की घोषणा बजट में हुई उनको बजट के बाद की चर्चाओं में सभी ने सराहा है।

इन सबके बीच एक बात जो थोड़ी दबी रह गई, वह है वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में हाल ही में भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों को लेकर हुए समझौते का जिक्र करते हुए एक प्रकार से भारत के कुशल कामगारों के लिए विदेशों में सृजित होने वाले अवसरों को रेखांकित करना। दरअसल यह एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि विदेशी निवेश के मुकाबले कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा देश में लाने के बावजूद प्रवासी भारतीय श्रमिकों की चर्चा उतनी नहीं होती है, जितनी विदेशी व्यापार और निवेश के छोटे-छोटे मुद्दों की होती है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व के सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाले देशों यानी विदेशों में कार्यरत प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली रकम में से एक है। वर्ष 2020 में भी भारत को करीब 75 अरब अमेरिकी डॉलर मिलने का

अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार अगर हम इन मजदूरों के योगदान की तुलना अनिवासी भारतीयों, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों, जिनकी चर्चा भी इन मजदूरों से कहीं ज्यादा होती है, उससे करें तो पता चलता है कि निजी तौर पर अनिवासी भारतीय अपनी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा शायद भारत के लिए लगाते हैं, जबकि ये मजदूर अपने जीवन का बड़ा हिस्सा भले जीवन निर्वहन के लिए विदेशों में खर्च करते हैं, परंतु अपना लगभग सारा निवेश भारत में ही करते हैं।

राजनीतिक रूप से देखें तो अनिवासी भारतीय देश के नागरिक नहीं हैं, जबकि ये कामगार इस देश के नागरिक हैं। यानी राजनीतिक प्रक्रिया में भी ये सीधी दखल रखते हैं। योगदान और अधिकार दोनों ही मामलों में इन कामगारों की किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। वैसे इस मामले में एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के देशों की यात्र के दौरान भारतीय कामगारों के योगदान का जिक्र कई बार किया और उन्हें भारत व खाड़ी देशों के बीच का सेतु माना। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन कामगारों से जुड़ी समस्याओं को लेकर काफी ध्यान दिया और कई बार विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में उनकी सराहनीय भूमिका रही है। विदेशों में भारत के कुशल श्रमिकों के लिए व्यापक अवसर हैं और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। यह सोच नई नहीं है। हमारे यहां से विदेशों में रोजगार के अवसरों को देखने और उनके फायदे उठाने की सोच पुरानी है। ब्रिटिश काल में हमारे देश से बड़ी संख्या में कामगार रोजगार की तलाश में अनेक देश गए। खाड़ी देशों में तेल मिलने के बाद जब कामगारों की जरूरत महसूस हुई तो पिछली सदी के छठे और सातवें दशक में केरल से बहुत बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में वहां गए। यह सिलसिला पिछली सदी के आठवें दशक में उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा, जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और तेल से आए पैसे को ये देश अपनी आधारभूत संरचना के विकास में लगाने लगे। इसके लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत थी जिसकी इन देशों में अनुपलब्धता थी, लिहाजा भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में कामगारों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हुआ। खाड़ी देशों में रोजगार के ज्यादा अवसर और ज्यादा वेतन के कारण धीरे-धीरे यहां से जाने वाले कामगारों की संख्या बढ़ती गई। केरल की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करने वाले इन प्रवासी मजदूरों ने इस राज्य को संपन्न राज्य बना दिया।

इसके बाद प्रवासन की एक दूसरी धारा सिलिकॉन वैली की ओर गई। वर्ष 1990 के बाद सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में व्यापक मांग सृजित होने के कारण भारत से बड़ी संख्या में पेशेवर कामगार अमेरिका गए। हालांकि इनमें से अनेक भारतीय तो वहीं के नागरिक हो गए, परंतु ज्यादातर भारत लौटे और यहां सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कंपनियां बना कर रोजगार प्रदाता भी बने। सरकार के स्तर पर भी इस सोच को मान्यता मिली और पूर्व में योजना आयोग ने जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के अनुपात का भारत और विश्व के बीच तुलनात्मक अध्यन करते हुए यह माना था कि अगर हमारा देश अपनी युवा शक्ति को कुशल बना ले, तो कुशल श्रमिकों के मामले में हम दुनिया की राजधानी के रूप में विकसित हो सकते हैं। वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में भाजपा के आने के बाद जिन मुद्दों को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है, उनमें से एक कौशल विकास का रहा। कौशल विकास के लिए नए मंत्रलय का गठन हुआ और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई। भारत के कुशल कामगारों को विभिन्न देशों में काम मिल सके, उनके कौशल को लेकर कोई संशय की स्थिति न हो इसके लिए सरकार ने न सिर्फ कौशल विकास प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई देशों मसलन जर्मनी, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन आदि के साथ समझौते किए, बल्कि हमारे देश में प्रशिक्षित लोगों को दुनिया में कहीं भी काम मिल सके उसके लिए मानकों और प्रमाणों के बीच एकरूपता कायम करने का भी प्रयास किया। इसके साथ-साथ विभिन्न देशों के साथ समझौतों में भी कुशल कामगारों के आवागमन और उनके काम करने को लेकर कानूनी अड़चन नहीं आए। इसके लिए भी विशेष प्रविधान किए गए। उन प्रयासों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों को लेकर हुए समझौते के अतिरिक्त अब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के कुशल कामगारों को अपने यहां रोजगार देने में रूचि दिखाई है।

विश्व के तकनीकी दिग्गज देश भी भारतीय मजदूरों की कुशलता का लोहा मान रहे हैं। भारत सरकार के साथ इन देशों द्वारा किए जाने वाले समझौतों से यह स्पष्ट हो रहा है। इससे हमारे श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर तो बनेंगे ही, साथ ही एक निश्चित अवधि के बाद जब ये श्रमिक वापस आएंगे तो अपने साथ नई तकनीकों से संबंधित अनुभव भी लाएंगे जिसका उपयोग यहां किया जा सकता है।

कमजोर विपक्ष अपनी तर्कहीनता और सतही राजनीति से अपने को और कमजोर कर रहा है

देश के मौजूदा हालात और खास तौर से दिल्ली के आसपास किसान संगठनों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए यह माना जा रहा था कि संसद का बजट सत्र हंगामे के चलते बर्बाद हो सकता है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विपक्ष को साधते हुए संसद की कार्यवाही को कामकाज लायक बनाए रखा। इसके चलते दोनों सदनों में बखूबी कामकाज हुआ। उत्पादकता के लिहाज से बजट सत्र का पहला हिस्सा खासा सफल कहा जा सकता है। थोड़ा-बहुत शोर-शराबा और हंगामा तो संसद में होता ही है। ऐसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन वह मुख्यत~ लोकसभा तक अधिक सीमित दिखा। लोकसभा में हंगामा करके विपक्ष ने अपने को बेनकाब ही किया, क्योंकि राष्ट्रपति के जिस अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई थी, उस पर लोकसभा में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में विपक्ष की ओर से कृषि कानूनों और किसानों पर बातें तो बहुत की गईं, लेकिन लगता है वह तैयारी से नहीं आया या फिर उसके पास इन कानूनों के खिलाफ कहने के लिए कुछ ठोस नहीं था। वह कुल मिलाकर वही निराधार आरोप दोहराता रहा, जो किसान नेता उछालने में लगे हुए हैं। जैसे राज्यसभा में विपक्ष कृषि मंत्री के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर कथित काले कानूनों में काला क्या है, वैसे ही वह लोकसभा में प्रधानमंत्री के इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहा कि कोई यह बताए कि इन कानूनों में कमी क्या है? प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर विचार करने लायक कोई कमी होगी तो उस पर गौर किया जाएगा। इसके बाद भी विपक्षी दल यह नहीं बता सके कि आखिर इन कानूनों में खराबी क्या है और है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? विपक्ष ने आरोप तो खूब लगाए, लेकिन किसी मसले पर ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे देश का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। कृषि कानूनों पर किसानों को उकसाने में लगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में तो भाग नहीं लिया, लेकिन बजट पर अपने विचार रखते समय कृषि कानूनों पर बोले। इस दौरान भी वह इन कानूनों की कथित खामियों पर प्रकाश नहीं डाल पाए। इसके बजाय उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा उछालकर सरकार पर कटाक्ष किया और कृषि कानूनों को लेकर हास्यास्पद आरोप लगाए। उनकी मानें तो सरकार इन कानूनों के जरिये किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं देना चाहती, अनाज की जमाखोरी कराना चाहती है और उद्योगपतियों की जेब भरना चाहती है। ये सब वही बेतुकी बातें हैं, जो वह न जाने कब से दोहरा रहे हैं। ऐसी बातें करके राहुल अपनी खोखली सोच को ही उजागर कर रहे हैं। यह निराशाजनक है कि जब विपक्ष से तर्क और तुक की बात करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह निराधार और मनगढ़ंत आरोप उछालता है। ऐसा करने से वह चर्चा में तो आ जाता है, लेकिन इससे विमर्श का स्तर गिरता है और जनता को कुछ हासिल नहीं होता। भाजपा और मोदी सरकार विपक्ष से लगातार पूछ रही है कि आखिर लोकसभा चुनावों के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसी तरह के कृषि कानूनों का वादा क्यों किया था, जैसे कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। खुद राहुल भी जवाब देने से इन्कार कर रहे हैं। इसके बजाय वह यह जुमला दोहराने में लगे हैं कि यह सरकार चंद उद्यमियों के फायदे के लिए चलाई जा रही है। यह सुखद है कि एक ऐसे समय जब राहुल गांधी उद्यमियों को गाली देने और उन्हें खलनायक की तरह पेश करने में लगे हुए हैं, तब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बिना किसी लाग-लपेट यह कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और देश को ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा जो धन अर्जन करते हैं। आखिर जब धन होगा तभी तो उसे गरीबों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सोच गुजरे जमाने की है कि सब कुछ सरकार करे। जैसी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद राहुल नए सिरे से उद्योगपतियों को बुरा बताने लगे। उनकी बातों से यही पता चलता है कि अति वामपंथ से ग्रस्त कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि आज के दौर में कोई भी देश निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता।

यह अच्छा हुआ कि बजट की बेतुकी आलोचना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में कांग्रेस के साथ-साथ राहुल गांधी को भी खरी-खरी सुनाई और दामाद का जिक्र करके उन्हें यह अच्छे से समझाया कि क्रोनी कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है। उन्होंने राहुल के हम दो हमारे दो जुमले का भी सटीक जवाब दिया। एक जमाना था जब उद्योगपतियों की पूंजी को काली कमाई कहकर लांछित किया जाता था और सस्ती राजनीति की जाती थी। यह जमाना लद चुका है और आज ऐसा करना उद्यमशीलता पर चोट करने के अलावा और कुछ नहीं। सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं, उनके लिए प्रभावी नियम-कानून बनाना और यह देखना है कि उनका उल्लंघन न हो। यह भी समझा जाना चाहिए कि निजीकरण के बिना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं होने वाला। समस्या यह है कि राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस भी यह भूलती जा रही है कि कैसे नरसिंह राव के समय मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को खोलने का काम किया था? इससे देश को लाभ मिला, लेकिन राहुल इसकी अनदेखी ही कर रहे हैं। लगता है वह अब भी उसी युग में जी रहे, जब गरीबी को महिमामंडित कर उद्योगपतियों को कठघरे में खड़ा किया जाता था।

ग्रीनकार्ड की गुंजाइश

बाइडन प्रशासन की ओर से पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद में पेश किया गया नागरिकता बिल 2021 इस बात की एक और स्पष्ट घोषणा है कि अमेरिका संकीर्णता को बाय-बाय बोलकर उदारता और खुलेपन की राह पर बढ़ चला है। यह विधेयक न केवल एच 1-बी वीजा धारी भारतीयों के हक में है बल्कि वहां अवैध तौर पर रह रहे लाखों प्रवासियों को नई उम्मीद दिलाता है। विधेयक के मुताबिक इन अवैध प्रवासियों को वहां अस्थायी हैसियत से पांच साल बिताने के बाद ग्रीनकार्ड के योग्य मान लिया जाएगा और पुलिस जांच वगैरह से निकलने तथा नियमित टैक्स भरने पर तीन साल बाद वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि यह बिल ज्यों का त्यों पास हो गया तो एक करोड़ से ज्यादा प्रवासियों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह खुल जाएगी। हालांकि फिलहाल ऐसा हो पाना मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि सीनेट में डेमोक्रैट्स के पास आवश्यक बहुमत नहीं है। लेकिन बाइडन प्रशासन इसे लेकर काफी गंभीर है और विधेयक में कुछ संशोधनों पर खुले मन से विचार करने की तैयारी भी दिखा रहा है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में साफ होगा कि अंततः किन संशोधनों के साथ विधेयक के कितने प्रावधानों को मंजूरी मिलती है।

अलबत्ता इतना तय है कि यह बिल संसद के अंदर ही नहीं, अमेरिकी समाज में भी तीखी बहस का कारण बनेगा। पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी जैसे सवालों को लेकर अमेरिका का एक श्वेत श्रमजीवी तबका काफी मुखर रहा है। उसकी शिकायत रही है कि प्रवासियों को तरजीह देने वाली नीतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। ट्रंप के शासनकाल में वीजा से जुड़े कुछ फैसले इस तबके को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में ही देखे गए थे। बहुत संभव है कि निम्न मध्यमवर्ग का यह हिस्सा इस विधेयक को भी अपने हितों पर हमले के रूप में देखे। मगर इससे अलग एक बड़ी सचाई यह है कि अमेरिकी समाज प्रवासियों के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। उसे न केवल रोज के छोटे-मोटे और हीन समझे जाने वाले कार्यों के लिए बल्कि विज्ञान और तकनीक में आगे रहने के लिए भी प्रवासियों की जरूरत है। दुनिया भर से आने वाले स्किल्ड प्रफेशनल और टैलंटेड रिसर्चर विभिन्न क्षेत्रों में उसका अग्रणी बने रहना मुमकिन बनाते हैं। इस अर्थ में देखें तो अपनी भौगोलिक सीमाओं में बंधे रहने की संकीर्णता आज दुनिया के हर समाज के आगे बढ़ने की राह में बाधा ही खड़ी करती है। अगर समाज का कोई हिस्सा असुरक्षित महसूस करता है तो जरूरत उसकी उस असुरक्षा को दूर करने की है, न कि इसे भुनाते हुए उसके अनुरूप नीतियां बनाने की। नागरिकता विधेयक पेश करके बाइडन प्रशासन ने नीतियों की दिशा सही करने का संकेत तो दे दिया है। देखने की बात यह होगी कि स्वस्थ बहस के जरिए इन नीतियों को सर्वस्वीकार्य बनाने का मकसद वह किस तरह से और किस हद तक हासिल कर पाता है।

मोदी के भावुक संबोधन की भले ही सियासी व्याख्या की जाए मगर इससे सुखद संदेश गया

> प्रधानमंत्री के भाषण का भाव सुस्पष्ट है, लेकिन सिसकियों के कारण बहुत कुछ अनकहा अनसुना रह गया है कि-हम भारत के लोग सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष एक ही भारत माता के पुत्र हैं। हम उत्तर-दक्षिण-पूरब-पश्चिम एक हैं। मत पंथ की भिन्नता के बावजूद एक हैं। दल परस्पर शत्रु नहीं हैं। एक सामान्य मूल्य बोध के कारण सब अपने हैं। इस मूल्य बोध को विकसित करने का काम सभी वर्गों के पूर्वजों ने किया। परस्पर मिलकर रहना ही आत्मनिर्भर समृद्ध भारत की गारंटी है।

संवेदनशीलता विशिष्ट मानवीय गुण है जो भावुकता में अभिव्यक्त होता है। यह नैसर्गिक है। इसे सप्रयास अर्जित नहीं किया जा सकता। कभी-कभी अनायास अंतर्मन में आत्मभाव के मेघ उठते हैं। चित्त मधुमयता से भर जाता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ तो प्राय~ नहीं ही होता है। बीते सप्ताह राज्यसभा में आत्मीय भावुकता का प्रेमपूर्ण दृश्य दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई के अवसर पर बोलते हुए भावुक हो गए। रोए और फफके। सदन विस्मित और आश्चर्यचकित था। मोदी संवेदनशील हैं। पहली बार लोकसभा पहुंचे तो संसद के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए संसद भवन की सीढ़ियों पर उसे साष्टांग प्रणाम किया। देश में लंबे अर्से से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य तनातनी है। आत्मभाव की अभिव्यक्ति दुर्लभ है। संसदीय परंपरा के लिए यह घटना मील का पत्थर है। इसकी राजनीतिक व्याख्या भी संभव है, लेकिन इसने देश के प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सुखद संदेश दिया है।

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, परंतु वे परस्पर शत्रु नहीं होते, लेकिन हाल में राजनीतिक विमर्श की भाषा शत्रुतापूर्ण हो गई है। चैनलों व अन्य मंचों पर वे दिन भर शत्रु की भाषा बोलते हैं। विचारधाराओं पर बहस नहीं होती। व्यक्तिगत आक्षेप और उत्तेजना राजनीतिक विमर्श की भाषा है। समूचा राजनीतिक तंत्र तनाव की स्थिति में है। बंगाल इसका ताजा

उदाहरण है। वाद-प्रतिवाद वहां गाली, गोली और हिंसा तक पहुंच गया है। ऐसी ही स्थिति अन्य स्थानों पर भी है। दलों की निचली इकाइयों तक परस्पर शत्रु भाव का विस्तार हो गया है। उन्माद संस्थागत हो रहा है। थोड़ी सी भीड़ ही विस्फोटक उत्तेजना के लिए काफी है। अराजकता या हिंसा स्थायी भाव बन रही है। कार्यकर्ता उस पर गर्व करने लगे हैं।

लोकतंत्र आत्मीयता और संवाद से चलता है, लेकिन सदनों के भीतर होने वाले संवाद यदाकदा बाधित रहते हैं। नए कृषि कानूनों पर भी युद्ध जैसी स्थिति है। सरकार आरंभ से वार्ता के लिए तैयार रही है, मगर दूसरा पक्ष उदासीन है। उलटे शत्रु देश को लाभ पहुंचाने वाली टीका-टिप्पणियां हुई हैं जबकि राष्ट्रीय प्रश्नों पर सभी दलों को एक होना चाहिए। कोरोना महामारी में कुशल प्रबंधन व प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है, लेकिन मोदी के प्रति शत्रुभाव रखने के कारण ऐसी उपलब्धियां नकार दी गई हैं। इस सबका मूल कारण संवादहीनता है और संवादहीनता का मूल कारण परस्पर शत्रुभाव। चुनाव जनतंत्र का मुख्य संवैधानिक उत्सव होता है। 15-20 वर्ष पहले तक चुनाव के दिनों में सभी दलों में आक्रामकता बढ़ जाती थी। अप्रिय नारेबाजी भी होती थी। कहीं-कहीं भिड़ंत भी होती थी। बाकी समय माहौल शांत रहता था। चुनाव आयोग बीच में आ गया तो चुनाव के दिनों का तनाव घट गया। अब बारह महीने चुनाव जैसा तनाव है। कलह है। अपशब्द हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान का अभाव है। आरोप प्रत्यारोप हैं। आरोप भी तथ्यहीन हैं। इनसे समग्र राजनीतिक वातावरण दूषित रहता है।

भारत का हर नागरिक समान है। उनकी उपलब्धियां निजी परिश्रम व राजव्यवस्था द्वारा उपलब्ध अवसरों का प्रतिफल हैं, पर जाति अलग तथ्य है। जाति जन्म के साथ मिलती है। इससे त्यागपत्र संभव नहीं है। जाति राष्ट्रीय एकता में बाधक है। जाति आधारित राजनीतिक विभाजन से तनाव बढ़ता है। राजनीति में इसका दुरुपयोग जारी है। मोदी जी ने परिवारवाद-जातिवाद पर कई बार खुलकर प्रहार किया है। प्रथमद्रष्टया सभी दल जाति के विरोधी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब करते हैं। जाति विभाजन राष्ट्रीय एकता का शत्रु है। समाज के प्रत्येक सदस्य के मन में समता और समरसता का भाव फैलाना श्रमसाध्य है और यह काम परस्पर शत्रु मानने वाले दलों के नेताओं द्वारा संभव नहीं है। दलों में आत्मीय भाव और संवाद बढ़ाने से ही समाधान होगा। संविधान की उद्देशिका में भारत के प्रत्येक नागरिक को हम 'भारत के लोग' कहा गया है, लेकिन अभी 'भारत के लोग' की संवैधानिक भावना का विकास नहीं हो पाया है। जाति अस्मिता, क्षेत्र अस्मिता, पंथ अस्मिता और भाषा अस्मिता हैं। ये समाज तोड़क हैं।

संसद और विधानमंडल भाग्यविधाता हैं, लेकिन यहां अब शोर और बाधाएं हैं। विपक्ष को बहस नहीं व्यवधान प्रिय लगता है। सदन में बहस होती तो देश को लाभ होता है। अब यहां कोई सुनने नहीं आता। इसलिए बहस में उत्तेजना स्वाभाविक है। संसदीय व्यवस्था को अब अग्नि स्नान की जरूरत है। संसद के समय का अधिकतम सदुपयोग करना सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। यह दोनों पक्षों के बीच आत्मीयता और अनौपचारिक प्रेम भाव में ही संभव है।

भारत प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो रहा है, परंतु राजनीतिक विभाजन का प्रभाव आम जनों पर भी पड़ रहा है। यह समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद एक भाषण में कहा था, 'यह समय अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका युवाओं, वृद्धों का है। धनी और गरीबों का ब्यूरोक्रेट और रिपब्लिकन का श्वेत और अश्वेत का भी है। लातिनों, एशियाई और अन्य विदेशी अमेरिकियों का है। हम राज्यों का संकलन नहीं। हम अमेरिकी हैं, अमेरिकी ही रहेंगे।' अमेरिका वास्तव में राज्यों का संकलन है और भारत स्वयं बनाए गए राज्यों का संघ, लेकिन भारत के राज्य मनमाना आचरण करते हैं। जिस विषय पर कानून बनाने का उनको अधिकार नहीं उस पर भी कानून बना डाल रहे हैं। संसदीय कानूनों को मानने से इन्कार करना संविधान विरोधी आचरण है। प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कोरोना सहित तमाम अवसरों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श लिया है, लेकिन मोदी को शत्रु मानने वाले विपक्ष ने व्यक्तिगत हमले को ही विपक्ष का संवैधानिक कर्तव्य माना है।

प्रधानमंत्री के भाषण का भाव सुस्पष्ट है, लेकिन सिसकियों के कारण बहुत कुछ अनकहा अनसुना रह गया है कि-हम भारत के लोग सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष एक ही भारत माता के पुत्र हैं। हम उत्तर-दक्षिण-पूरब-पश्चिम एक हैं। मत पंथ की भिन्नता के बावजूद एक हैं। दल परस्पर शत्रु नहीं हैं। एक सामान्य मूल्य बोध के कारण सब अपने हैं। इस मूल्य बोध को विकसित करने का काम सभी वर्गों के पूर्वजों ने किया। परस्पर मिलकर रहना ही आत्मनिर्भर समृद्ध भारत की गारंटी है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

राहुल गांधी के बयान पर बिहार विधान परिषद में पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर हुई नोक-झोंक

पटना । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड के सांसद राहुल गांधी के एक कथित बयान को लेकर बुधवार (24 फरवरी) को विधान परिषद में जमकर शोर-शराबा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्य इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव की मांग करने लगे तो विपक्ष ने खुलकर इसका प्रतिवाद किया। दोनों पक्षों के शोर शराबे में 15 मिनट तक सदन डुबा रहा। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के संजय प्रकाश ने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्रम की एक सभा में कांग्रेस नेता राहलु गांधी ने उत्तर भारत के लोगों को नासमझ बताया है। उन्होंने इसे उत्तर भारत खासकर बिहार का अपमान बताते हुए परिषद में इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसका विरोध करते हुए खंडन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पुरानी बातों को दुहराते हुए कहा कि किसी पर अंगुली उठाने के पहले भाजपा नेता को अपनी पार्टी के नेता के वक्तव्य पर विचार करना चाहिए।

उधर, राजद के रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि किसी भी सदन के सदस्य पर चर्चा दूसरे सदन में नहीं होनी चाहिए। खासकर बड़े दल के नेता के बारे में ऐसी चर्चा सही नहीं है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि पूर्वे की बात सही है लेकिन अगर बिहार की अस्मिता को ठेस लगे तो उसपर चर्चा करने से परहेज नहीं होनी चाहिए। आखिरी में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पूर्वे के सुझाव पर सहमति व्यक्ति करते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया।

पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनेंगे 25 हजार मकान, ये होंगे नियम और शर्तें

चंडीगढ़ । पंजाब कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25000 से अधिक मकान बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस नीति के तहत डेवलपर्स और अथारिटी की ओर से ईडब्ल्यूएस हाऊसिंग के लिए प्रोजेक्ट क्षेत्र का पांच फीसद निर्माण अपेक्षित होगा। ब्रिकलैस तकनीक से मकानों का निर्माण उचित आकार और उचित स्थानों में किया जाएगा। इसके लिए योग्य प्रोजेक्ट प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) की सेवाएं ली जाएंगी।

योग्य लाभार्थियों को पंजाब में जन्म का प्रमाण या अर्जी देने की तारीख से 10 साल पहले राज्य में रिहायश का प्रमाण देना होगा। समय-समय पर भारत सरकार या पंजाब सरकार की तरफ से संशोधित किए गए नियमों अनुसार सभी स्त्रोतों से पारिवारिक आय तीन लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक (पति /पत्नी या नाबालिग बच्चे) के नाम पर पंजाब या चंडीगढ़ में पहले से ही कोई भी फ्री होल्ड, लीज होल्ड रिहायशी प्लाट, बसेरा यूनिट नहीं होना चाहिए। आवेदक को इन पहलुओं पर स्व-तस्दीक करनी होगी। मोटरव्हीकल कर की वसूली और इसके रिफंड की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए कैबिनेट ने पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1924 (संशोधित) के सेक्शन तीन और शेड्यूल में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह संशोधन मोटर कार या मोटर साइकिल मालिक की तरफ से किसी अन्य राज्य में वाहन समेत प्रवास कर जाने और पंजाब का निवासी न रहने या पंजाब से बाहर निवास करते किसी व्यक्ति के नाम मालिकाना हक तबदील करने की सूरत में अदा किए जाने वाले एकमुश्त कर के रिफंड जैसे मुद्दों से संबंधित है। अगर ट्रांसपोर्ट वाहन पंजाब के अलावा किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हैं तो ऐसे वाहन की तरफ से पंजाब में दाखिले के समय उस दर पर कर (टैक्स) की अदायगी की जाएगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है। इसी तरह नए स्टेज कैरिज परमिट जारी करते समय ऐसी बसों पर प्रति किलोमीटर की दर से एक बार का कर वसूला जाएगा। जब भी किसी बड़ी बस के मालिक को बढ़ाए गए रूट पर बढ़ी माइलेज के साथ बस चलाने की आज्ञा दी जाएगी तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक बार कर की वसूली की जाएगी।

लुधियाना में पिता व उनके पार्टनर की एफडी अपने खाते में ट्रांफसर करवा साढ़े आठ लाख रुपये ठगे

लुधियाना । माडल टाउन निवासी व्यक्ति ने अपने पिता की मौत के बाद उनके पार्टनर दोस्त के साथ कराई एफडी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करके लाखों की ठगी की। अब थाना डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। एएसआइ जागीर सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान माडल टाउन निवासी यसमिंदर सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस ने गिल रोड के मुरादपुरा की गली नंबर 5 निवासी चरणजीत सिंह की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस कमिश्नर को अगस्त 2019 में दी शिकायत में चरणजीत सिंह ने बताया कि आरोपित उनके स्वर्गीय दोस्त स्वर्ण सिंह का बेटा है। चरणजीत सिंह व उनके दोस्त स्वर्ण सिंह ने मिल कर बैंक में 8,50,740 रुपये की एफडी कराई थी। मगर उसी बीच जुलाई 2017 में उनके दोस्त स्वर्ण सिंह का देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद 10 जनवरी 2018 में उस एफडी के मैच्योर होने के बाद उनके बेटे यसमिंदर सिंह ने उस रकम को अपने पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। बाद में उनके चेक का दुरुपयोग करते हुए सारी रकम अपने खाते में ट्रांसफर करके उनके साथ धोखाधड़ी की है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने आरोप सही पाए जाने पर आरोपित पर केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी। डीए लीगल की राय लेने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है।

सीतामढ़ी में एक घर पर दस बदमाशों का हमला, लूटपाट, घर में लगा दी आग

सीतामढ़ी (रुन्नीसैदपुर) । सीतामढ़ी में इन दिनों बदमाश बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। कहीं लूटपाठ हो रही तो कही गोलीबारी। इन घटनाओं से लोग सहमे हुए है। थाना क्षेत्र के ओयना गांव में बुधवार की रात बदमाशों ने उप मुखिया भोला सिंह के घर पर धावा बोल दिया। गृहस्वामी के अनुसार, करीब दस की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने हथियार के बल पर उन्हें बंधक बना लिया। अंदर आंगन में प्रवेश कर लूटपाट मचाई। इस दौरान बदमाशों को महज दस ग्राम सोने के आभूषण व कुछ मूल्यवान कपड़े ही मिले। गृहस्वामी का पूरा परिवार डुमरा स्थित आवास पर रहता है ।इसलिए यहां कुछ विशेष नहीं था। बदमाशों ने तलाशी के दौरान ट्रंक व ब्रीफकेस को खोल उसमें रखे सामानों को इधर-उधर व अस्त-व्यस्त कर दिया ।इस बीच मौका मिलते ही गृहस्वामी गांव की ओर भागा। मदद में हल्ला मचाते ग्रामीण जबतक मौके पर पहुंचे बदमाश घर में आग लगाकर वहां से फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।

झारखंड में उग्रवादी हिंसा से जुड़े आश्रितों को दो-दो बार मुआवजा, केंद्र ने वापस मांगे पैसे...

रांची । उग्रवादी हिंसा के शिकार आठ लोगों के आश्रितों में मुआवजे की राशि दोबारा बांट दी गई। प्रत्येक आश्रित को तीन लाख रुपये मुआवजा के हिसाब से कुल 24 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। इसका खुलासा केंद्रीय ऑडिट में हुआ है। अब केंद्र सरकार ने अतिरिक्त भुगतान से संबंधित अपनी राशि वापस करने के लिए राज्य सरकार से पत्राचार किया है।

उग्रवादी हिंसा में मरने वालों के आश्रित के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में तीन लाख रुपये प्रति मृतक देने का प्रावधान है। सभी आठ मृतकों के आश्रितों को 2011 से 2013 के बीच 24 लाख रुपये का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था। इसके बावजूद रांची जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतते हुए 2018 व 2019 में दो बार में कुल 24 लाख रुपये का भुगतान फिर कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इंटरनल ऑडिट विंग ने इस अनियमितता को पकड़ा और अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली की अनुशंसा की है।

प्रदेश में स्कूलों में कोरोना संक्रमण के केस मिलने पर अलर्ट, अब होगी फोकस टेस्टिंग

लखनऊ । राजधानी लखनऊ के लामार्टीनियर ब्वॉयज कॉलेज के साथ प्रयागराज के एक स्कूल में स्टाफ के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से योगी आदित्यनाथ सरकार हाई अलर्ट पर है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार ने फोकस टेस्टिंग को बढ़ाया है। इसके तहत स्कूल-कॉलेजों में रैंडम सैम्पलिंग होगी। अब अगले 4 दिनों तक संस्थानों में रैंडम जांच की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना देने के लिए सभी होटल को भी निर्देश दिया गया है।

लखनऊ में लामार्टीनियर ब्वॉयज कॉलेज में स्टॉफ के छह सदस्य व प्रयागराज के दो स्कूलों में स्टॉफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब फोकस टेस्टिंग के तहत चलाए जा रहे अभियान में स्कूल-कॉलेजों में अधिक सैंपल लिए जाएंगे। फोकस टेस्टिंग के तहत पंद्रह दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोडने के लिए अभियान को और तेज किया जाएगा।

एक मार्च से प्रदेश में कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग और चौकन्ना हो गया है। दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर और सर्तकता बरती जा रही है। अब तो जिलों में स्कूल-कॉलेजों के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजारों में रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। पहले यह अभियान गुरुवार तक चलाया जाना था लेकिन इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रदेश में अब हर शहर में होटल में मेहमानों के आते ही जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। प्रदेश सरकार ने अब कोरोना के दूसरे अटैक को रोकने के लिए सख्ती कर दी है। किसी भी शहर में महाराष्ट्र, केरल व पंजाब सहित कहीं से भी आने वाले मेहमानों के होटल में चेक इन से पहले होटल प्रबंधन को जिला प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी। देश के कई राज्यों में कोरोना का दूसरा अटैक हो गया है और इसके उत्तर प्रदेश में भी फैलने की आशंका में सरकार पहले से तैयारी कर रही है।

प्रदेश में अब हर शहर में होटल में मेहमानों के आते ही जिला प्रशासन को सूचना देनी होगी। प्रदेश सरकार ने अब कोरोना के दूसरे अटैक को रोकने के लिए सख्ती कर दी है।

आदेश हैं कि होटल प्रबंधन किसी के भी आगमन की पुलिस को सूचना दे।

महाराष्ट्र, केरल व मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में दोबारा कोरोना वायरस संक्रमण के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार भी अलर्ट पर है। यहां दोबारा कोरोना संक्रमण बढने से रोकने के लिए फिर से सख्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना को लेकर ढिलाई बिल्कुल भी न बरतने की हिदायत दी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जैसे मार्च 2020 में संक्रमण फैलने पर बचाव के उपाय और सख्ती की जा रही थी, वैसे ही कठोर कदम फिर से उठाए जाएं। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन करने के नियम का बेहद सख्ती से पालन कराया जाएगा। मोहल्ला व ग्राम निगरानी कमेटियों को फिर से अलर्ट कर दिया गया है। वह बाहर से आने वालों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को देंगे।

स्वास्थ्य विभाग पहले ही प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे मरीजों में से 10 फीसद के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला कर चुका है। नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सैंपल राजधानी स्थित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) भेजे जाएंगे। केजीएमयू के माइक्रोबॉयोलॉजी लैब इसके लिए तैयारी कर चुकी है। वहीं जरूरत पडने पर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बॉयोलॉजी (आइजीआइबी) को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ सख्ती भी बरती जाएगी।

टेस्टिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग पर फोकस- स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टेस्टिंग व कांटेक्ट ट्रेसिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है और अधिकतम 1.3 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जरूरत पडने पर इसे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में अब तक तीन करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट और 15.3 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।

अस्पताल भी हुए सतर्क, लेवल वन होंगे शुरू- कोरोना संक्रमण के लगातार घटने के कारण प्रदेश में लेवल वन के अस्पताल बंद कर दिए गए थे। अब लेवल टू व लेवल थ्री के अस्पतालों में ही करीब 18 हजार बेड हैं। पहले सितंबर 2020 में सर्वाधिक 68,235 केस होने पर लेवल वन से लेकर लेवल थ्री तक के अस्पतालों में 1.5 लाख बेड की व्यवस्था की गई थी। हलांकि एक्टिव केस अब केवल 2190 हैं, लेकिन फिर भी जरूरत के अनुसार कोरोना के कम गंभीर मरीजों के लिए सीमित दायरे में लेवल वन की सुविधा शुरू होगी।

छूटे फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी कोरोना वैक्सीन - उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज न लेने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगेगी। अब तक छूटे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। अब 2 लाख 40 हजार से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन होना है। इसके लिए 2731 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल के दौरे का कार्यक्रम तय, दो को मालदा में करेंगे चुनावी सभा

लखनऊ । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहत के बीच बेहद सक्रिय हो चुकी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को धार देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र के बीच में भी एक दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती देने मालदा जाएंगे। यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा करीब 1500 रैली करेगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह पहला बंगाल दौरा होगा। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान वह सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो मार्च को पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के साथ ही एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा में कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी बिहार, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ तथा केरल में भी अपनी धारदार शैली में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भी शिरकत की थी। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल आने का कार्यक्रम था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने वहां पर उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पश्चिम बंगाल में बेहद सक्रिय होने के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना जलवा दिखाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हो चुके सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केरल का भी दौरा किया था। केरल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के साथ ही उन्होंने जनसभा भी की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अपनी ओजस्वी शैली के धाराप्रवाह संबोधन से विपक्ष के नेताओं की अक्सर ही चुटकी लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अभी आगे के भी कार्यक्रम तय होंगे।

विधानसभा में विधायक को नीतीश ने किया निरुत्तर, बोले-उधर अकेले पड़ जाएंगे, मिल-बैठकर बात करिए

पटना । बिहार विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के कारण कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाया। उससे पहले मंगलवार को सदन में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों का अभिभाषण काफी रोचक रहा। धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तर्कपूर्ण जवाब सबको निरुत्तर कर गया। एआइएमआइएम विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान को उन्होंने दो टूक बता दिया कि उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार में कोई दूसरी राजधानी नहीं हो सकती। दरअसल, उसकी दरकार ही नहीं। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट ईमान एआइएमआइएम विधायकों के साथ सदन से बाहर जाने लगे। मुख्यमंत्री ने चुटकी ली। उधर जाकर अकेले पड़ जाएंगे। इधर आइए और मिल-बैठकर बात करिए। वैसे भी आप जदयू और राजद होते हुए तीसरी पार्टी में गए हैं।

फिलहाल मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया की राजनीतिक हलके में अलग-अलग व्याख्या हो रही। उसका एक आधार जनवरी में एआइएमआइएम विधायकों की नीतीश से भेंट-मुलाकात भी है। तब भी एआइएमआइएम विधायकों के इधर-उधर होने की चर्चा हुई थी। हालांकि तब ईमान ने स्पष्ट कर दिया था कि साथी विधायकों के साथ वे क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। खुद नीतीश ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे सांसद-विधायक व विधान पार्षद आदि मिलते रहते हैं। उसका कोई अतिरिक्त आशय नहीं होता।

दो राजधानी की जरूरत कहां...

भाषण के दौरान एआइएमआइएम विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान सदन से बाहर जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने टोका-आप कहां जा रहे हैं। आपको कोई काम हो तो आइए। मिल कर बताइए। हां, पूर्णियां को राजधानी बनाने की आपकी मांग बकवास है। वह नहीं होगा। दो राजधानी की जरूरत कहां है। पहले रांची दूसरी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन तब झारखंड का अस्तित्व नहीं था। बिहार का दायरा बड़ा होने के कारण रांची को दूसरी राजधानी बनाना पड़ा था। अब राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक पांच घंटे में पहुंचा जा सकता है। सुविधाओं में निरंतर विकास हो रहा। ऐसे में बिहार के लिए दूसरी राजधानी की जरूरत नहीं। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा तो कतई संभव नहीं। मेरे बाद अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता है तो वह उसकी इछा।

आगरा पुलिस से बचने के लिए 28 दिन तक पांच राज्यों में ली लव जिहाद के आरोपित ने शरण

आगरा । आगरा पुलिस को चकमा देने के लिए युवती को अगवा करने के आरोपित सलमान ने 28 दिनों में पांच राज्यों की शरण ली। किसी भी जगह सप्ताह भर से ज्यादा नही रुका। इसके बावजूद लव जिहाद के आरोपित सलमान को पुलिस ने उसे खोज निकाला। बुधवार की दोपहर उसे आइएसबीटी पर घेराबंदी करके दबोच लिया। युवती को भी बरामद कर लिया है। उसने पुलिस को दिए बयान में सलमान पर बहला फुसलाकर करके ले जाने का आरोप लगाया। युवती का कहना है कि आरोपित ने उसे अपने रिश्तेदारो और परिचितों के यहां जबरन बंधक बनाकर रखा था।

वहीं, आरोपित सलमान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह 27 तारीख की रात को युवती को लेकर भागने के बाद सीधे प्रयागराज गया था। इसी दौरान उसे शाहगज में बाजार बंद कराने और धरना-प्रदर्शन का पता चला तो वह दिल्ली भाग गया। उसे आभास हो गया था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसलिए वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा था। उसने दिल्ली, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में शरण ली।

आगरा पुलिस द्वारा लगातार दबिश देने और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसने से वह परेशान हो गया था। उसे लगने लगा था कि पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है। इसलिए लौटकर आगरा आया था। पुलिस ने आरोपित को अदालत में प्रस्तुत किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं युवती का मेडिकल कराने के बाद पुलिस उसे अदालत में बयान दर्ज कराने को प्रस्तुत करेगी।

ये है मामला- शाहगंज क्षेत्र निवासी युवती 27 जनवरी की आधी रात को गायब हो गई थी। पिता ने सोरों कटरा निवासी सलमान कुरैशी के खिलाफ पुत्री को अगवा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए 28 जनवरी को बाजार बंद करा दिया था। वह परिवार वालों के साथ धरने पर बैठ गए थे। अधिकारियों द्वारा आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देने के बाद लोग धरने से उठे थे। इंस्पेक्टर शाहगंज सत्येंद्र सिंह राघव ने बताया आरोपित सलमान की गिरफ्तारी को पांच टीम लगी थीं। बुधवार को तीसरे पहर सलमान और युवती के आइएसबीटी पर पहुंचने का पता चला। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपित को दबोच लिया। युवती को भी बरामद कर लिया है।

आरोपित सलमान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि युवती को ले जाने के बाद उसे पता था कि पुलिस परिवार को परेशान करेगी। इसके चलते उसने परिवार को 26 जनवरी की शाम को ही रिश्तेदारी में भेज दिया था। उसका अनुमान सही निकला। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों और परिचितों के यहां दबिश दीं।

नोएडा के 3500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले का आरोपी बीएन तिवारी लखनऊ से गिरफ्तार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम के साथ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने काफी चर्चा में चल रहे 3500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड के साथी हिंदी न्यूज चैनल के मालिक बीएन तिवारी को लखनऊ से गुरुवार को गिरफ्तार किया है। बीएन तिवारी लाइव टुडे न्यूज चैनल का मालिक भी है। बीएन तिवारी पर प्रदेश के इस बड़े घोटाले में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद अब नोएडा में पेश किया जाएगा।

बाइक बैंक घोटाले के आरोपी 50 हजार के इनामी बीएन तिवारी को गोमती नगर से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ कर रही है। बीएन तिवारी के खिलाफ नोएडा में बाइक बोट घोटाले में दो दर्जन से अधिक एफआईआर में से दो में आरोप पत्र भी दाखिल है। नोएडा के साथ लखनऊ में भी बीएन तिवारी पर बाइक बोट घोटाले की एक एफआईआर दर्ज है। लंबे समय से फरार चल रहे बीएन तिवारी को यूपी एसटीएफ ने आज दबोच लिया। अब उसे नोएडा के दादरी थाने में पेश किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 3500 करोड़ रुपया के बाइक बोट घोटाले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने आज बीएन तिवारी को गिरफ्तार किया है। इस बड़े घोटाले में अब तक एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने भारी व्यवधानों के बाद भी आखिरकार बीएन तिवारी को गिरफ्तार किया है। 3500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले के सरगना बीएन तिवारी पर 50 हजार रुपया का इनाम भी घोषित किया गया था। इस बड़े घोटाले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। इससे पहले नोएडा के चर्चित बाइक बोट घोटाले को लेकर ईडी ने बीते शनिवार को बीएन तिवारी और उनके बेटे कुश तिवारी के लखनऊ में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की टीम ने गोमतीनगर और पारा क्षेत्र में छापेमारी की।

थानेदार की विधायक से बदसलूकी पर सदन में उठा मामला, तेजस्वी बोले-राबड़ी आवास पर भी की बदतमीजी

पटना । विधानसभा परिसर में मीडिया को बयान देते वक्त भाकपा माले विधायक महबूब आलम के साथ थानेदार की बदसलूकी का मामला गुरुवार को सदन में उठा। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया कि इस मामले को दिखवाया जाए। अधिकारी अगर दोषी पाए गए तो विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई होगी। इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले इसी अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मिलने आने वाले लोगों के साथ बदतमीजी की थी।

सदन में विधायक महबूब के मामले उठाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साथ दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से उक्त अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है। सदन की गरिमा का सवाल है। जनहित के मकसद से लाखों लोग चुनकर हम सबको सदन में भेजते हैं, किंतु अधिकारी ने एक विधायक के साथ जिस तरह से धक्का-मुक्की की वह जनता का अपमान है। तेजस्वी ने बताया कि कुछ दिन पहले इसी अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर मिलने आने वाले लोगों के साथ बदतमीजी की थी। इसकी सूचना उन्हें भी मिली थी। इसलिए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

थानेदार ने की धक्का-मुक्की, मीडिया से भी दुर्व्यवहार-

राजद नेता तेजस्वी यादव से पहले माले विधायक महबूब आलम ने सदन को अवगत कराया कि बुधवार को जब वह विधानसभा परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे तो उक्त थानेदार ने आकर उनके साथ धक्का-मुक्की की। इतना ही नहीं मीडिया से भी थानेदार ने दुर्व्यवहार किया। महबूब ने उक्त थानेदार पर कार्रवाई की मांग की। इसपर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह गंभीर मामला है। इसे देखा जाना चाहिए, जो नियम बनाया गया है, उसका अनुपालन होना चाहिए। उसमें जो भी बाधक बनेगा, उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई होगी।

एक थानेदार, दो दारोगा समेत 15 पुलिस वाले सस्पेंड, रात की वसूली में बिगड़ा खेल, दो सिपाही गए जेल

आरा । भोजपुर यानी आरा जिले के थाना वाहनों में लगे कैमरा युक्त जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ने आखिरकार वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का सारा खेल बिगाड़ दिया। ट्रकों से अवैध वसूली के चक्कर में एक थानेदार व तीन एएसआई समेत 15 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिर गई। जबकि, दो चालक सिपाहियों को एफआइआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी भोजपुर एसपी हर किशोर राय ने बुधवार को दी। एसपी की इस सख्ती के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। गौरतलब हो कि हाल के दिनों में पहले भी पांच पुलिसकर्मी उगाही के चक्कर में जेल जा चुके है।

रात में पेट्रोलिंग में निकले थे पर कर रहे थे वसूली

बताया जाता हैं कि चांदी थाना का गश्ती दल रोज की तरह नाइट पेट्रोलिंग में निकला हुआ था। जिला बल का ड्राइवर शिव कुमार को कैमरा युक्त जीपीएस सिस्टम से ट्रक ड्राइवरों से पैसा वसूलते देखा गया। इसके बाद जांच में पकड़े जाने पर चालक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि, अन्य पेट्रोलिंग पार्टी एएसआई असरफी लाल को निलंबित कर दिया गया।

इसके अलावा होमगार्ड जवान गुमानी सिंह, राजेश्वरी मिश्रा तथा सूर्यवंश राय को छह महीने के लिए ड्यूटी से हटा दिया गया है। इसी तरह संदेश थाना के होमगार्ड चालक धनंजय यादव को ट्रक ड्राइवरों से पैसा वसूलने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि, पेट्रोलिंग पार्टी एएसआई दिलीप पासवान, डीएपी जवान जनार्दन कुमार, संजीत यादव व विजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

बताया जाता है कि पीरो अनुमंडल के इमादपुर थाना में निजी ड्राइवर धीरज गुप्ता सरकारी वाहन चला रहा था। गश्ती के दौरान ट्रक ड्राइवरों से पैसा वसूली करने में लगा था। इस मामले में इमादपुर थानाध्यक्ष साजिद अंसारी, पेट्रोलिंग अधिकारी एएसआई सदानंद पांडेय , बीएमपी जवान संजीत चौधरी, जय प्रकाश पाल और डीएपी सिपाही शिव कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने बताया 23 फरवरी की रात में जिन थाना के गाड़ियों में कैमरा युक्त जीपीएस सिस्टम लगा है, उसे चेक किया गया। जिसमें तीन मामले प्रतिवेदित हुए है। जिस पर कार्रवाई की गई है।

एक नजर

गेहूं उर्पाजन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि आज

जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले के किसानों से आग्रह किया है कि वे गेहूँ उर्पाजन के लिए ई ,उर्पाजन पोर्टल पर आज ही अपना पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने की गुरूवार 25 फरवरी अंतिम तिथि है। कलेक्टर ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2021.22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए किसान अपना पंजीयन समिति स्तर पर बनाए गए केन्द्रों, लोक सेवा केन्द्रों, एमपी ऑनलाइन के कियोस्क एवं कृषि उपज मंडी समितियों में करा सकते हैं। किसानों के पंजीयन की सुविधा के लिए ये केन्द्र सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर खोले गए थे।

सीआईआई मॉडल कैरियर सेंटर में प्लेसमेंट ड्राइव कल

जबलपुर। राज्य शासन के आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश 2020 अभियान के अंतर्गत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर निगम एवं सीआईआई के संयुक्त तत्वावधान में शक्ति भवन, रामपुर में तरंग ऑडिटोरियम के सामने स्थित सीआईआई मॉडल कैरियर सेंटर जबलपुर में शुक्रवार 26 फरवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेंट ड्राइव में निजी क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स के नियोजकों द्वारा विभिन्न रोजगार अवसरों हेतु भर्ती की जाएगी। समस्त 18 से 30 वर्ष तक की आयु की 10वीं, 12वीं, स्नातक, पीजीडीसीए, डीसीए, एमसी, उत्तीर्ण इच्छुक युवा अपने आधार एवं बायोडाटा के साथ प्लेसमेंट ड्राइव में उपस्थित होकर लाभ ले सकते हैं। कोविड.19 के तहत सतर्कता हेतु मास्क पहनकर आना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

आरडीयू परिसर में भवन निर्माण अनियमित्ताओं की शिकायत

जबलपुर। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी परिसर में कई भवनों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमित्तायें सामने आ रही हैं। उपरोक्त शिकायत यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ सदस्यों ने बुधवार को कुलपति, कुलसचिव को शिकायत सौंपकर की गई। लिखित शिकायत में यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद कुशवाहा, कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल ने बताया कि गुणवत्ताविहीन कार्यों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यूनिवर्सिटी कैंटीन के उपर प्रथम तल का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन कार्यों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की नजरअंदाजी से असंतोष पनप रहा है। यदि इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो समस्त कर्मचारी इसकी लिखित शिकायत उच्च शिक्षा मंत्री के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्रालय को करेंगे।

वर्षों से नहीं हुई पेंशनर्स फोरम की बैठक, कैसे सुलझेंगी समस्याएं

जबलपुर। विगत कई वर्षों से पेंशनर्स फोरम की बैठक ही आयोजित नहीं की गई। इससे चलते स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के पेंशनर्स की समस्याएं बढ़ रही हैं। उपरोक्त शिकायत पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से की गई। पेंशनर्स एसो. द्वारा कमिशनर से संभागीय पेंशनर्स फोरम की बैठक शीघ्र आमंत्रित करने की मांग की है। पेंशनर्स एसो. जिला शाखा अध्यक्ष पं. नरेश उपाध्याय, संभागीय अध्यक्ष व्ही.पी. शुक्ला, आरके प्यासी, आरएल पाण्डेय, डीएस गुप्ता, प्रेम वल्लभ शर्मा, केके शुक्ला, बीबी शर्मा आदि ने बताया कि पेंशनर्स फोरम की बैठक न होने से लंबित पेंशनर्स समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। संगठन ने इस संदर्भ में शीघ्र बैठक आयोजित करने की मांग की है।

बालाघाट में भी रुकेगी रीवा-इतवारी स्पेशल ट्रेन

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के रीवा से इतवारी (नागपुर) के बीच शुरू हुई नई ट्रेन का बालाघाट स्टेशन पर ठहराव नहीं दिए जाने का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। बालाघाट के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को रेलमंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया था। जिसके बाद रेलवे ने इस नई ट्रेन का बालाघाट स्टेशन पर हाल्ट देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पमरे जबलपुर प्रियंका दीक्षित ने बताया कि गाड़ी संख्या 01754-01753 रीवा-इतवारी-रीवा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का ठहराव बालाघाट स्टेशन पर देने का निर्णय लिया गया है।

बालाघाट में 5 मिनिट रुकेगी- गाड़ी संख्या 01754 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस सुबह 4.30 बजे बालाघाट पहुंचकर 4.35 बजे गोंदिया की ओर रवाना होगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 01753 इतवारी-रीवा एक्सप्रेस रात 21.45 बजे बालाघाट पहुंचेगी, जहां से रात्रि को 21.50 बजे जबलपुर की ओर रवाना होगी।

केंद्र और राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल एक जनहित याचिका में किसानों के हित संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित करे ताकि किसानों की आत्महत्या के मामलों में कमी आए।

वकील शिव कुमार त्रिपाठी की ओर से दाखिल इस याचिका में केंद्र सरकार के साथ सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में बताया गया है कि 2019 में कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 10,281 लोगों ने आत्महत्या की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1995 से 2015 के बीच 2,96,438 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। भारत के ज्यादातर किसान कमजोर तबके से हैं और इन लोगों को संरक्षित करना राज्य का दायित्व है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कानून पारित हुआ था। इन कानूनों के तहत आयोगों का गठन हुआ, लेकिन आज तक किसानों के लिए किसी स्थायी आयोग का गठन नहीं हुआ। जबकि प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले एक आयोग की सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि किसानों की समस्याओं पर सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किसानों के प्रतिनिधित्व के साथ राज्य स्तर पर किसान आयोग गठित किए जाएं।

स्वामीनाथन रिपोर्ट को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार की ओर से किसान आयोग (विधायी संस्था) गठित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केंद्र और राज्य स्तर पर तत्काल प्रभाव ने विधायी संस्था किसान आयोग गठित किए जाने की जरूरत है जो किसानों के हितों को देखे और उनकी समस्याओं पर विचार करे।

देश के 19 राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं

नई दिल्ली । देश में पिछले 24 घंटे में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,46,907 है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.33 प्रतिशत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 13,742 मामले सामने आए जबकि इसी दौरान 14,037 लोग उपचार के बाद ठीक हुए। इससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 399 मामलों की गिरावट आई है।

पिछले एक सप्ताह में 12 राज्यों में रोजाना औसतन 1000 से ज्यादा नए मामले आए। इनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली और हरियाणा शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक केरल और महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह रोजाना औसतन 4,000 मामले आए।

पिछले 24 घंटे में जिन 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से किसी की मौत नहीं हुई है उनमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, चंडीगढ़, असम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली शामिल हैं।

भारत में 1,07,26,702 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने वाले 86.26 प्रतिशत मरीज छह राज्यों के हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5869 लोग स्वस्थ हो गए जबकि केरल में 4823 लोगों ने संक्रमण को मात दी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6218 नए मामले आए। वहीं केरल से 4034 और तमिलनाडु से 442 मामले आए।

पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण से 104 और लोगों की मौत हो गयी। मौत के 81.73 प्रतिशत मामले पांच राज्यों के थे।

पूरे देश में आज भारत बंद, 8 करोड़ व्यापारियों की हड़ताल, बाजार रहेंगे बंद; ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम

नई दिल्ली, एजेंसियां । पूरे देश में कल यानि 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच कल पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा। देशभर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के आठ करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी इसी दिन 'चक्का जाम' का ऐलान किया है। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है।

जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में इसी दिन 'चक्का जाम' का ऐलान किया है। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे।

ट्रांसपोर्टरों संगठन भी इस दौरान हड़ताल में शामिल होंगे। सभी राज्य स्तरीय-परिवहन संघों ने भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए ई-वे बिल कानूनों के विरोध में कैट का समर्थन किया है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने कार्यालयों को इस दौरान पूरी तरह बंद रखने की घोषणा की है। किसी भी प्रकार की माल की बुकिंग, डिलीवरी,

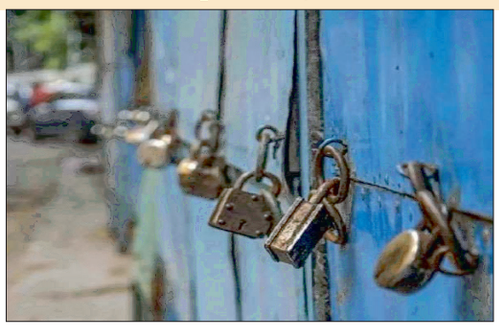

लदाई/उतराई बंद रहेगी। सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से शाम के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा है।

कल देश भर में 1500 जगहों पर व्यापारी संगठनों का धरना होगा। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद से माल एवं सेवा कर के कठोर प्रावधानों को समाप्त करने की मांग को लेकर 26 फरवरी को देश भर में 1500 स्थानों पर धरना भी दिया जाएगा. देश भर के सभी बाजार बंद रहेंगे और सभी राज्यों के अलग-अलग शहरों में विरोध स्वरूप धरना का आयोजन किया जाएगा।

देशभर के व्यापारी संगठनों की हड़ताल

इस भारत बंद में देश भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा बड़ी संख्या में कई राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है, जिसमें खास तौर पर ऑल इंडिया एफएमसीज़ी डिस्ट्रिब्यूटर्ज़ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ अलूमिनियीयम यूटेंसिलस मैन्यूफैकचरस एंड ट्रेडर्ज एसोसिएशन, नार्थ इंडिया स्पाईसिस ट्रेडर्स एसोसिएशन, आल इंडिया वूमेंन एंटेरप्रिनियर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया कम्प्यूटर डीलर एसोसीइएशन, आल इंडिया कॉस्मेटिक मनुफक्चरर्स एसोसिएशन आदि संगठन शामिल हैं।

चीन की हर चाल पर भारत की नजर, फिंगर एरिया में अब ड्रैगन नहीं कर पाएगा कोई गुस्ताखी, सेना कर रही हाईटेक निगरानी

नई दिल्ली । पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके से भारत-चीन की सेनाओं की वापसी के बाद वहां शांति है। हालांकि, भारत की तरफ से इस क्षेत्र की गहन और हाईटेक निगरानी की जा रही है। सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि फिंगर-3 क्षेत्र, जहां भारतीय सेना अभी तैनात है, वहां ऊंचे स्थानों से दूरबीन और नाइट विजन उपकरणों की मदद से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिंगर-3 की ऊंची पहाड़ियों से पूरे इलाके पर नजर रखना संभव है। इसके अलावा अत्याधुनिक ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जिनके जरिये पूरे क्षेत्र पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं समझौते के तहत ही पीछे हटी हैं, लेकिन भारतीय सेना हर प्रकार से एहतियात बरत रही है।

134 किलोमीटर दायरे में फैला है इलाका

भारतीय सेना अब फिंगर-3 के निकट धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आ चुकी है, जबकि चीनी फौज फिंगर-8 तक पीछे हट चुकी है। फिंगर-1 से फिंगर-8 तक का पूरा इलाका 134 किलोमीटर लंबा है। जो इलाका खाली हुआ है, वह भी तकरीबन सौ किलोमीटर के दायरे में फैला है।

गश्त पर अस्थाई रोक लगाई गई

तय समझौते के तहत इस क्षेत्र में अस्थाई तौर पर गश्त स्थगित रखी गई है। भारतीय सेना फिंगर-8 और चीन की सेना फिंगर-4 तक गश्त करती थी। सूत्रों ने कहा कि इसके शुरू होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले टकराव के अन्य बिन्दुओं, जिनमें डेप्सांग (डेपसांग), डेमचौक, हॉट स्प्रिंग और गोगरा शामिल हैं, उन पर सारा ध्यान है। पिछली बैठक में भी इन्हीं पर जोर दिया गया था।

डेप्सांग और डेमचौके का मुद्दा जटिल

सूत्रों के मुताबिक, हाट स्प्रिंग और गोगरा में सेनाएं पहले ही काफी हद तक पीछे हट चुकी हैं। वहां पर मई से पूर्व की स्थिति बहाल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। अलबत्ता डेप्सांग और डेमचौके के मुद्दे जटिल हैं। उन्हें सुलझाने में अभी वक्त लग सकता है। सूत्रों ने कहा कि भारत-चीन में अगले कुछ दिनों में 11वें दौर की बैठक हो सकती है। या फिर विदेश मंत्रालयों के बीच बनी संयुक्त समिति आपस में चर्चा कर सकती है।

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत खोले जाएंगे नए केंद्र

निगमायुक्त ने निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा

जबलपुर। 26 फरवरी 2021 को अपरान्ह 03:00 बजे से भोपाल मिन्टो हॉल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से नए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत स्थापित केन्द्रों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश भर में 100 और जबलपुर में 4 नए केन्द्रों का लोकार्पण होगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत नगर निगम के प्रशासक बी चन्द्रशेखर, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के द्वारा राजागोकुलदास धर्मशाला में पूर्व से संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना केन्द्रों के साथ-साथ 4 नए केन्द्रों की स्थापना कराई गई है।

आईएसबीटी बस स्टैण्ड, पिसनहारी की मढ़िया, कृषि उपज मण्डी एवं सामुदायिक भवन बड़ा पत्थर रांझी, जहां 26 फरवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाकर शहरी गरीबों के लिए रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। जिसकी तैयारियों के संबंध निगमायुक्त संदीप जीआर ने उपरोक्त सभी स्थलों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोकार्पण कार्यक्रम के पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन समक्ष में प्रस्तुत की जावे। उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के मौके पर निगमायुक्त संदीप जी आर के साथ अपर आयुक्त परमेश जलोटे, संभागीय अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह, सत्येन्द्र चक्रवर्ती, सिटी मिशन मैनेजर मंजुला गोंटिया आदि उपस्थित रहें।

गुजरात में जीत से ओवैसी के बदले तेवर, पीएम मोदी को नसीहत व भाजपा को दी चेतावनी

अहमदाबाद । मनपा चुनाव में सफलता मिलते ही एआइएमआइएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के तेवर बदल गए। मंगलवार देर रात गोधरा में हुई चुनावी सभा में सीएए, किसान कानूनों तथा तीन तलाक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्ते तेहादुल मुस्लेमीन पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी नगर पालिका व पंचायत चुनाव का प्रचार करने मंगलवार को गोधरा पहुंचे थे। 1857 की क्रांति में मुसलमान उलेमाओं के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी बता रहे हैं। ओवैसी ने कहा मैं तो जब तक जिंदा हूं आंदोलनजीवी ही बनकर रहूंगा।

उनकी पार्टी की ओर से गिनी चुनी सीटों पर ही उम्मीदवार उतारने पर कटाक्ष करने वालों पर पलटवाकर करते हुए ओवैसी ने कहा कि जंगल में शेर तो एक ही होता है, जब शेर जंगल में निकलता है तो जानवर अपने आप रास्ता कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब वे संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो 543 सदस्यों में से कई यह सोचकर सतर्क हो जाते हैं कि ये शेरवानी, दाढी, टोपी वाला जाने वाले या बोलेगा।

औवैसी यहीं नहीं रुके, वे बोले ये लोग मुझ पर ताना मारते हैं कि आप तो दो-दो बीवियों वाले हो, इस पर औवैसी कहते हैं कि भाई मैं तो एक से परेशान हूं। तीन तलाक पर औवैसी ने कहा आपको मुस्लिम औरतों की चिंता कब से होने लगी। अगर तीन तलाक कानून मान्य ही नहीं है तो इसे अपराध कैसे मान लिया गया। मुस्लिमों के मत लेकर भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसी नेताओं को आडे हाथ लेते हुए कहा कि क्या गजब एक्टर हैं। ढाई साल हीरो बनते हो और फिर खुद बिकने चले जाते हो।

ओवैसी ने गोधरा की मुस्लिम बस्तियों में स्कूल, अस्पताल, सफाई व अन्य सुविधाएं नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसा सबका साथ सबका विकास है। रेल पटरी के एक ओर नगर पालिका खूब विकास करा रही है और दूसरी ओर कोई काम नहीं। धर्म के आधार पर भेदभाव संविधान का उल्लंघन है। वे बोले लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनें तो ही उनका विकास होगा लेकिन सेकेंडरी के बाद स्कूल ही नहीं है तो कैसे आगे पढ़ सकेंगी। ओवैसी ने मोदी को किसानों से बातचीत करने की नसीहत देते हुए एक शेर पढ़ते हुए भाषण खत्म किया, सितमगर की नजर से निजर मिलाकर जिएं, अगर दो दिन कम जिएं। इसमें हैरत के या, हम उनके साथ थे जो शमा जलाकर दिए।

26 फरवरी को केट के प्रस्तावित बंद को मिला व्यापारिक संगठनों का समर्थन

जीएसटी के 4 वर्ष, 937 संशोधनः व्यापारी वर्ग में भरा आक्रोश

जबलपुर, (एजेंसी)। जीएसटी आने के पहले जिम्मेदारों द्वारा इस बात को खूब प्रचारित किया गया था कि इस कानून के बाद पूरे देश में एकरूपता वाली टैक्स प्रणाली लागू होगी। व्यापारी वर्ग को बार-बार टैक्स भरने से राहत मिलेगी, लेकिन हुआ उससे उलट। बीते 4 वर्षों में जीएसटी में करीब 937 संशोधनों ने आम व्यापारी को परेशान कर ही दिया है साथ ही साथ इससे कर प्रणाली विशेषज्ञ भी हैरान-परेशान हैं।

उपरोक्त वक्तव्य कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट) पदाधिकारियों ने बुधवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में व्यक्त किए। केट पदाधिकारियों ने बताया कि केट द्वारा पूरे भारतवर्ष में 26 फरवरी को हड़ताल प्रस्तावित की गई है जिसका

समर्थन नगर के समस्त व्यापार मंडल एवं व्यापार एसोसिएशन ने किया है। जीएसटी नियम के उल्लंघन पर बैंक खाता और सम्पत्ति जप्त करने बात से पूरे व्यापारी वग्र में आक्रोश है। ये हड़ताल जीएसटी विसंगतियों तथा ऑनलाईन व्यापार के बढ़ते दुष्प्रभाव पर की जा रही है।

जीएसटी नियमों को लेकर तेजी से बढ़ा आक्रोश

पत्रकारवार्ता में केट प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष संदेश जैन, संभागीय अध्यक्ष जितेन्द्र पचौरी, जिलाध्यक्ष दीपक सेठी ने बताया कि जीएसटी में कोई भी संशोधन लाने के पहले व्यापारियों से किसी भी विषय में कोई बातचीत नहीं की और न ही जीएसटी को लेकर व्यापारियों की परेशानियों को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। वर्तमान में जीएसटी का जो स्वरूप है, यदि उसके विरोध में आज कोई आवाज नहीं उठाई गई तो व्यापार करना बेहद मुश्किल हो जायेगा। केट पदाधिकारियों ने बताया कि महाकोशल चेम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर शहर के अधिकांश व्यापारी संघों व संगठनों की ओर से 26 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन दिया गया है। हड़ताल के दौरान सभी व्यापारी सिविक सेंटर में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के नाम जीएसटी विसंगतियों और ऑनलाईन व्यापार से हो रही परेशानियों से अवगत भी करायेंगे।

प्रवासी मजदूरों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, विस्तृत रिपोर्ट पेश न होने पर जिम्मेदार अधिकारी होंगे तलब

जबलपुर **(एजेंसी)।**

वैष्विक महामारी कोरोना के कारण प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप लगाते हुए दायर मामले को हाईकोर्ट ने काफी सख्ती से लिया।

चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष बुधवार को पूर्व आदेश के परिपालन में सरकार की ओर से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने समय की राहत चाही गई। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि मामले की अगली सुनवाई दौरान विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया जाएगा, विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। उल्लेखनीय है कि यह जनहित याचिका बधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस के कारण दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश में लौट रहे है। प्रवासी मजदूरों को खादय तथा आर्थिक मदद करने के लिए कई शासकीय योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे प्रवासी मजदूर अपना जीवन-यापन कर सकें।

याचिका में कहा गया है कि दूसरे प्रदेश से लौटे प्रवासी मजूदरों को किसी प्रकार की शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका के साथ वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के नाम की सूची आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण प्रवासी मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि प्रदेश से लौटे प्रवासी मजदूरों की पंजीकृत संख्या लगभग 7 लाख 40 हजार है। जिसमें से लगभग 45 हजार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

पूर्व में युगलपीठ ने सरकार को प्रवासी मजदूरों की सुविधाएं संबंधित योजनाएं बढाने निर्देश दिए थे। याचिका की सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से पेश की गयी स्टेटस में आपत्ति उठाते हुए कहा गया कि किन-किन मजदूरों के खाते में कितनी राशि जमा की गयी, कितने मजदूरो को अनाज उपलब्ध करवाया गया। मनरेगा के तहत कितने प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी गयी आदि का स्पस्ष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। जिस पर न्यायालय ने सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले में आगे हुई सुनवाई पर न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए, जिसकी फिलहाल प्रतीक्षा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सन्नो शगुफता खान ने पैरवी की।

ट्विटर में हिन्दी भाषा को मान्यता क्यों नहीं

हाईकोर्ट में याचिका दायर, केंद्र सरकार को पक्ष रखने मोहलत

जबलपुर। ट्विटर द्वारा हिन्दी भाषा को मान्यता नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि हिन्दी भाषा को मान्यता नहीं दिए जाने के कारण विदेश में हिन्दी भाषा में किए गए ट्वीट को ट्रांसलेट कर दिखाते है। चीफजस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में केन्द्र सरकार को अपना पक्ष रखने चार सप्ताह की मोहलत दी है।

यह जनहित याचिका बालाघाट लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि ट्विटर ने 9 भाषा को मान्यता दी है। ट्विटर द्वारा हिन्दी भाषा को मान्यता नहीं दी गयी है। हिन्दी में किए जाने वाले ट्वीट तो हिन्दी में दिखाए जाते है परंतु विदेश में ट्रांसलेट कर उन्हें अंग्रेजी भाषा में दिखाया जाता है। जिसके कारण ज्यादातर अर्थ बदल जाते है। ट्विटर पर हिन्दी भाषा को मान्यता दिलवाने के संबंध में उन्होनें केन्द्रीय सूचना एव प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा था। केन्द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के मुलतवीं कर दी।

सैफ अली खान-करीना कपूर

के बेबी बर्थ के बाद

सारा अली खान

ने बिखेरा अपनी खूबसूरती का जलवा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नया फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने अपना ग्लैमरस अवतार दिखाया है। दरअसल, सारा ने एली इंडिया के लिए एक खूबसूरत फोटोशूट करवाया है। जिसमें उन्होंने अपना एक अलग ही अंदाज दिखाया है। एक से बढ़कर एक आउटफिट में वह अलग-अलग स्टाइल में पोज दे रही हैं। इन फोटो में वह कमाल की लग रही हैं।

ग्लैमरस अवतार में उनका हर रूप देखने लायक है। कैमरे के आगे अपनी अदाओं से खेलने की अदा सारा अली खान को बखूबी आती है। ऐसा ही कुछ वो इस फोटोशूट में भी करती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में कभी सारा अली खान ऑल ब्लैक आउफिट में नजर आ रही हैं तो कभी मल्टी कलर के आउटफिट में दिख रही हैं। हालांकि वह सभी फोटो में काफी खूबसूरत लग रही हैं। सारा का यह अंदाज इस महीने मैगजिन के डिजिटल कवर पेज नजर आने वाला है। उन्होंने फरवरी 2021 के लिए शूट करवाया है।आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अकसर अपने फोटो और वीडियो फैन्स के साथ साझा करती नजर आ जाती हैं। अब सारा के प्रोफेशन लाइफ की बात करें आपको बता दें कि सारा जल्द ही फिल्म अतरंगी रे में भी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस मशहूर एक्टर अक्षय कुमार और धनुष के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इससे पहले सारा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कुली नंबर वन में दिखीं थीं इस फिल्म में सारा अली खान वरुण धवन के साथ मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आई थीं। फिल्म में सारा अली खान और वरुण धवन की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया।

आपको बता दें कि सारा अली खान पटौदी खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। सारा बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान और अस्सी के दशक की एक्ट्रेस अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा के माता-पिता का तलाक वर्ष 2004 में हो गया था। सैफ ने अमृता से तलाक लेने के बाद एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी कर ली। हाल ही में एक्ट्रेस करीना एक और बेटे जन्म दिया है। इसकी वजह से आजकल पटौदी परिवार में खुशियों का महौल है।

Deepika Padukone

के बाद रणवीर सिंह पर चढ़ा 'पॉरी' का भूत, फैन संग गाजर का हलवा खाते हुए शेयर किया मजेदार वीडियो

_रणवीर यह डायलॉग बोल रहे होते हैं तभी पीछे से उन्हें एक लड़की ज्वॉइन करती है और सेम डायलॉग रिपीट करती है। वीडियो में रणवीर कलरफुल शर्ट और ब्लैक गॉगल में नजर आ रहे हैं। वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

इन दिनों हर किसी के सिर पर 'Pawri' का नशा चढ़ा हुआ है। हर कोई अपनी-अपनी स्टाइल में 'पॉरी' वीडियो बना रहा है। इसका भूत न सिर्फ आम लोगों पर चढ़ा है बल्कि सेलेब्स भी इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं। अबतक न जानें कितने स्टार्स 'पॉरी' वीडियो बना चुके हैं, जिन्हें उनके फैंस ने काफी पंसद भी किया। वहीं हाल ही में जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 'पॉरी' वीडियो को लेकर चर्चा में आईं थीं। वहीं अब उनके पति एक्टर एक्टर रणवीर सिंह पर भी 'Pawri' का नशा छा गया है। रणवीर का एक %पॉरी' वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनका अतरंगी अवतार फैंस को काफी पंसद आ रहा है।रणवीर सिंह का एक 'पॉरी' वीडियो इस वक्त काफी चर्चा में हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह हमेशा की तरह ही अपने अलग अंदाज में फैंस को सरप्राइज दे रहे हैं। वीडियो में रणवीर अपने एक फैन के साथ अपनी हलवा 'पॉरी' करते नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। इस दौरान रणवीर सिंह के हाथ में एक डब्बा नजर आ रहा है जिसमें हलवा है। वहीं उनके साथ उनकी फैन नजर आ रही है। दोनों ने इस दौरान मास्क पहना हुआ है। एक्टर का उनकी फैन के साथ उनकी बॉन्डिंग भी काफी पसंद की जा रही है।वीडियो में रणवीर सिंह गाजर के हलवे का बॉक्स पकड़े हुए कहते हैं- 'ये हम हैं, ये हमारा गाजर का हलवा है और ये हमारी पार्टी हो रही है।' जब रणवीर यह डायलॉग बोल रहे होते हैं, तभी पीछे से उन्हें एक लड़की ज्वॉइन करती है और सेम डायलॉग रिपीट करती है। वीडियो में रणवीर कलरफुल शर्ट और ब्लैक गॉगल में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही इसपर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

Adhyayan Suman की खुदकुशी की खबर सुनकर होश खो बैठी थीं मां, एक्टर बोले- 'शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को'

बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन के बेटे एक्टर अध्ययन सुमन को लेकर हाल ही में एक फेक न्यूज़ वायरल हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। एक न्यूज़ चैनल ने अध्ययन की मौत को लेकर ये खबर चलाई जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। हालांकि बाद में पता चला कि न्यूज़ गलत है, जिसके बाद शेखर सुमन ने चैनल को जमकर लताड़ा और कहा कि वो इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। शेखर के बाद अध्ययन ने भी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो पूरी तरह ठीक हैं।

अब एक्टर ने एक बार फिर इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया है। एक्टर ने बताया कि जिस वक्त उनकी मां को ये खबर मिली तो उनकी क्या होलात हो गई थी। एक पैपराज़ी से बात करते हुए अध्ययन ने कहा, 'अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो ये क्या मेरा भूत आपसे बात कर रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है'।अध्ययन ने बताया, 'मुझे लोगों के कॉल आना शुरू हुए तब मैं मीटिंग में था। सब लोग घबरा गए थे, मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा था। मेरी मां को ये सुनकर धक्का लगा था, वो शॉक में थीं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इस खबर पर। फिर आखिरकार मैंने उनका फोटो उठाया। बल्कि मैं तो खुद अभी तक शॉक में हूं। मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे वजह क्या थी? क्यों आपने ये चलाया कि मैंने सुसाइड कर ली है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूं। आप किसी के बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकते हो आपको शर्म आनी चाहिए'।इससे पहले शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए लिखा था, 'हम बेहद व्यथित हैं और अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सके हैं। मैं सभी लोगों के चैनल के इस अक्षम्य व्यहार के ख़िलाफ़ ट्वीट और बैन करने की गुज़ारिश करता हूं। ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं उचित क़ानूनी कार्रवाई भी करने जा रहा हूं'।आगे उन्होंने लिखा, 'इस अक्षम्य काम के लिए चैनल के किसी पत्रकार द्वारा माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। बॉस लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए और इस बड़ी चूक को स्वीकार करना चाहिए। सोचिए, अगर उन्होंने ऐसा किसी बड़े नेता के साथ किया होता तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाता। पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फ़र्ज़ी न्यूज़ को बढ़ावा देने वाले सबसे ज़्यादा क्षति करते हैं और उन्हें दंडित करने की ज़रूरत है।

Shahid Kapoor की पत्नी मीरा राजपूत ने अपने चेहरे की चोट पर पहली बार की खुलकर बात, बताया कैसे आया निशान

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत उनकी तरह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस के लिए खास तस्वीर-वीडियो भी साझा करती रहती हैं। मीरा राजपूत अपनी निजी जिंदगी के बारे में खास खुलासे भी करती रहती हैं।

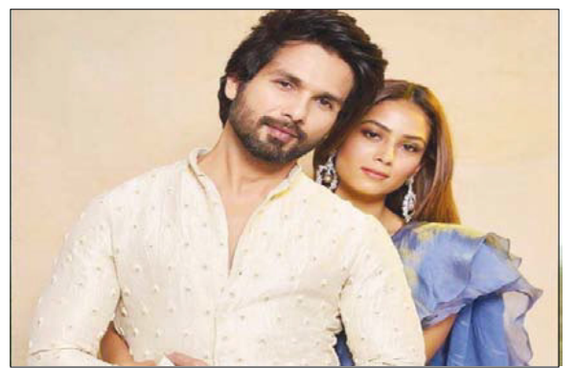

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत उनकी तरह हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने फैंस के लिए खास तस्वीर-वीडियो भी साझा करती रहती हैं। मीरा राजपूत अपनी निजी जिंदगी के बारे में खास खुलासे भी करती रहती हैं। अब वह पहली बार अपने चेहरे की एक चोट के निशान पर खुलकर बोली हैं।

मीरा राजपूत के माथे के बाईं तरफ एक चोट का निशान है। यह निशान अक्सर उनकी तस्वीरों में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने इस चोट के निशान को लेकर खुलकर बात की है। दरअसल मीरा राजपूत ने सोमवार को अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर खास सेशन किया था। इस दौरान उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही अपनी माथे ही चोट के बारे में भी बताया।मीरा राजपूत के एक फैन ने उनके माथे की चोट को लेकर सवाल किया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उन्हें यह चोट उस समय लगी थी जब वह कुल 3 साल की थी। मीरा राजपूत ने कहा, 'जब मैं तीन साल की थी सभी बच्चों की तरह मैं भी अपने बेड पर कुद रही थी। उसी दौरान मैं बेड से गिर गई थी और बेड के कोने से मुझे चोट लग गई थी। यह निशान मुझे वहीं मिला था' ।इसके अलावा मीरा राजपूत ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में और भी ढेर सारे मजेदार किस्सों को भी साझा किया है। उन्होंने अपने क्रश के बारे में भी बताया है। एक फैन ने मीरा राजपूत से उनके क्रश के बारे में सवाल किया।

इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्रिकेटर एबी डिविलियर्स का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वह उन्हें बहुत प्यार करती हैं। मीरा ने बताया कि उनका फेवरिट नेटफ्लिक्स शो शिट्स क्रीक बताया।

मीरा ने अपना पसंदीदा नाश्ता पोहा बताया।मीरा अपने परिवार में सबसे अधिक पसंद किसे करती हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके पापा उनके फेवरिट हैं। इसके अलावा मीरा राजपूर ने फैंस के और भी कई सवालों के जवाब दिए हैं। जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बीते दिनों मीरा राजपूत शाहिद कपूर के साथ अपने वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की वजह से चर्चा में थीं।

मार्टिन गुप्टिल ने रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

वेलिंग्टन, (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 4 रन से जीत दर्ज करते हुए 2-0 से बढ़त बना ली है। मैच में न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल (97) रन से अपनी शानदार पारी के कारण वह भारतीय ओपनर रोहित शर्मा का रिकार्ड तोड़ने में कामयाब रहे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

गुप्टिल ने अपनी पारी के दौरान 50 गेंदों का सामना करते हुए 97 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे और अब उनके नाम टीम क्रिकेट में सबसे ज्यादा 132 छक्के हो गए हैं। वहीं रोहित ने 127 छक्के लगाए हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि जहां गुप्टिल ने अभी तक 96 मैच खेले हैं वहीं भारतीय ओपनर (रोहित) ने 108 मैच खेले हैं। रोहित और गुप्टिल के अलावा फिलहाल किसी भी खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 120 छक्कों तक नहीं पहुंचा है। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुप्टिल, कप्तान केन विलियमसन (35 गेंदों पर 53 रन) और जेम्स नीशम (16 गेंदों पर 45 रन) की पारी की बदौलत 7 विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलिया को 220 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम जोश फिलिप (32 गेंदों में 45 रन), मार्कस स्टोइनिस (37 गेंदों पर 78 रन) और डैनियल सैम्स (15 गेंदों पर 41 रन) 8 विकेट गंवाकर ओवर खत्म होने तक 215 रन ही बना सकी और चार रन से हार गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 53 रन से जीत मिली थी।

डुनेडिन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए मार्टिन गुपटिल।

ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का टीकाकरण मार्च से

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को कोविड-19 के लिए अगले माह मार्च के अंत से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। खेल मंत्रालय ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोचों को प्राथमिकता सूची में रखने को कहा है । खेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार उन्होंने इसके लिए एक खाका तैयार कर लिया है तथा स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर उन्होंने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के टीकाकरण अगले महीने से शुरू करने की योजना बनायी है। एक अधिकारी ने कहा, खेल मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता सूची में रखने का आग्रह किया है। हमने खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ के दो चरणों में होने वाले टीकाकरण के लिये पहले ही योजना तैयार कर ली है। उन्होंने कहा, अभी हम स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जब भी हमें उनकी तरफ से मंजूरी मिलेगी हम अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर देंगे।अभी तक भारत के 74 खिलाड़ियों ने टोक्यो में 23 जुलाई से आठ अगस्त के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों के लिये क्वालीफाई किया है।

पृथ्वी ने विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। टीम इंडिया से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने मुम्बई की ओर से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शतक लगाया है। पृथ्वी ने पुडुचेरी के खिलाफ केवल 142 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया है। पृथ्वी ने पिछले तीन मैचों में दो शतक लगाये हैं। पृथ्वी ने अपनी पारी में 27 चौके और चार छक्के लगाए हैं। इस प्रकार विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले वह चौथे बल्लेबाज हो गये हैं। उनसे पहले सिर्फ संजू सैमसन ने नाबाद 212, यशस्वी जयसवाल ने 203 और कर्णवीर कौशल ने 202 रन बनाये थे। पिछले कुछ समय से खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर चल रहे पृथ्वी को इसी कारण इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जगह नहीं मिली है। अब अपनी इस पारी से वह एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहते हैं। पृथ्वी के अलावा सूर्यकुमार यादव ने भी पुडुचेरी के खिलाफ आक्रामक पारी खेली। सूर्यकुमार ने केवल 50 गेंदों में शतक लगा दिया। उन्होंने 58 गेंदों पर 229 की स्ट्राइक रेट से 133 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 22 चौके और चार छक्के लगाए हैं। सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ के बीच तीसरे विकेट के लिए 201 रनों की साझेदारी हुई। अपनी इस पारी के साथ ही सूर्यकुमार ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज में अपने चयन को सही साबित किया है।

वहीं, एक अन्य मैच में ग्रुप सी के एक अन्य मैच में केरल ने रेलवे को सात रन से हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज करके शीर्ष पर स्थिति और बेहतर की। इस दौरान अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोबिन उथप्पा ने तीन मैचों में अपना दूसरा शतक जमाया जबकि सलामी बल्लेबाज विष्णु विनोद ने 107 रन की पारी खेली थी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 193 रन बनाये।संजू सैमसन ने 61 और वत्सल गोविंद ने नाबाद 46 रन की पारियां खेली, जिससे केरल ने छह विकेट पर 351 रन बनाए। रेलवे ने मृणाल देवधर 79, अरिंदम घोष 64, सौरभ सिंह 0) और हर्ष त्यागी 58 के अर्धशतकों की मदद से अच्छा जवाब दिया लेकिन आखिर में उसकी टीम 49.4 ओवर में 344 रन पर आउट हो गयी।

इंग्लैंड ने अंपायरिंग का मसला मैच रैफरी श्रीनाथ के सामने रखा

अहमदाबाद, (एजेंसी)। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने भारत के खिलाफ मौजूदा दिन रात के टेस्ट में अंपायरिंग के स्तर का मसला मैच रैफरी जवागल श्रीनाथ के सामने उठाया, जिन्होंने कहा कि कप्तान मैदानी अंपायरों के सामने सही सवाल उठा रहे थे।इंग्लैंड की टीम तीसरे अंपायर सी शमसुद्दीन के दो फैसलों से नाराज थी। भारत के सलामी बल्लेबाज दूसरे ओवर में बेन स्टोक्स की कैच अपील से बच गए। इसके बाद रोहित शर्मा को स्टम्प आउट करने की बेन फोक्स की अपील खारिज कर दी गई।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इंग्लैंड के कप्तान और मुख्य कोच ने पहले दिन के खेल के बाद मैच रैफरी से बात की। कप्तान और मुख्य कोच ने अंपायरों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि फैसलों में निरंतरता होनी चाहिए। मैच रैफरी ने कहा कि कप्तान अंपायरों से सही सवाल कर रहे थे। गिल के मामले में कई तरह से फुटेज देखने के बाद उन्हें नाबाद करार दिया गया, जबकि रोहित को तुरंत ही नॉट आउट करार दे दिया गया। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जाक क्रॉली ने पहले दिन के खेल के बाद कहा कि जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तब जैक के मामले में उन्होंने पांच या छह कोणों से फुटेज देखी, लेकिन जब हम फील्डिंग कर रहे थे तो एक ही कोण से देखा। मैं नहीं कह सकता कि वे आउट थे या नहीं, लेकिन चेकिंग और बेहतर हो सकती थी।

अरूण कुमार ने अल्ट्रा-मैराथन रेस पूरी कर रिकार्ड बनाया

मुंबई, (एजेंसी)। अरूण कुमार भारद्वाज ने मुंबई-नासिक-पुणे अल्ट्रा-मैराथन रेस पूरी कर एक नया रिकार्ड बनाया है। अरूण ने महाराष्ट्र के तीन बड़े शहरो में लगातार 166 घंटे दौड़ कर 560 किलोमीटर की रेस पूरी की। अरूण ने पिछले कई सालों में कई लंबी रेस की दौड़ों में भाग लिया है और कई खिताब हासि किये हैं। इस बार अरूण का दौड़ में भाग लेने का लक्ष्य लोगों के बीच में स्वस्थ्य जीवन को लेकर संदेश फैलाना था। अरूण ने कहा कि भारत में दौड़ को लेकर पिछले कुछ सालों से चलन शुरू हुआ है। लोगों में संदेश देने के साथ ही स्वास्थ्य और फिटनेस, अल्ट्रा-मैराथन रन हमारे भविष्य के एथलीटों की सहायता करेंगे जो ओलंपिक में जगह पाने के लिए वे तैयारी कर रहें हैं। मैं रनिंग इसलिए करता हूं ताकि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित कर सकूं। बतौर एक अल्ट्रा मैराथॉन रनर होने मैंने दिन-ब-दिन कई सौ किलोमीटर तक दौड़ चुका हूं। उनका सबसे बढ़िया शौक लेह के रास्ते कारगिल से कन्याकुमारी तक 4100 किलोमीटर की दौड़ है जिसे पूरा करने में उन्हें दो महीने लगे। अरूण भारद्वाज ने लंबी दूरी की दौड़ के कई खिताब जीते हैं।

युवराज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह पर एससी-एसटी के तहत हांसी थाने में केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब युवराज ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए केस खारिज और हांसी पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आज सुनवाई की जाएगी।

युवराज के खिलाफ वकील और नेशनल अलायंस और दलित मन राइट्स के संयोजक रजत कलसन ने पिछले साल (2020) दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन जब पुलिस ने 8 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना हुई और पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया तो कलसन कोर्ट चले गए, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस ने आईपीसी एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली थी। गौरतलब है कि पिछले साल युवराज ने इंस्टाग्राम पर ओपनर रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट के दौरान युजवेंद्र चहल पर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। युवराज के ऐसा करने पर काफी बवाल मचा था और सोशल मीडिया पर युवराज सिंह माफी मांगो हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा था। इसके बाद युवराज ने ऐसा करने पर माफी भी मांगी थी।

भारत में होगा घुड़सवारी विश्व कप क्वालीफायर

नई दिल्ली, (संवाददाता)। 11 से 14 मार्च के बीच भारत में घुड़सवारी विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले होंगे। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इस टूनार्मेंट का आयोजन भारतीय घुड़सवारी महासंघ और इक्विविंग्स स्पोर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। इस टूनार्मेंट में मेजबान भारत सहित सात अन्य देशों के प्रतियोगी भा लेंगे जिसमें रूस, अमेरिका, बेलारूस, पाकिस्तान, सूडान और बहरीन शामिल हैं। इन 7 टीमों में से शीर्ष दो टीमें साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिये क्वालीफाई करेंगी।

स्टोक्स को गेंद पर लार लगाने के कारण अंपायर ने दी चेतावनी

अहमदाबाद, (एजेंसी)। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को यहां यहां भारतीय टीम के खिलाफ दिन-रात्रि के तीसरे टेस्ट के दौरान गेंद पर लार लगाने के कारण अंपायर ने चेतावनी दी। कोरोना महामारी को देखते हुए आईसीसी ने गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक लगाई हुई है। इस नियम का उल्लंघन करने पर चेतावनी के साथ ही अंतिम विकल्प के तौर पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। स्टोक्स को मैच के दौरान गेंद पर लार लगाते हुए देखा गया जिसके बाद गेंद को सैनिटाइज करना पड़ा। यह घटना 12वें ओवर के अंत में हुई जब स्टोक्स गेंद को चमकाने के लिये लार का इस्तेमाल करते दिखे जिससे अंपायर नितिन मेनन ने उन्हें फिर यह गलती न करने आगाह किया। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पिछले साल जून में कोविड-19 महामारी के चलते गेंद को चमकाने के लिये लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। आईसीसी के कोविड-19 दिशानिदेर्शों के अंतर्गत एक टीम को प्रत्येक पारी में दो बार चेतावनी दी जा सकती है लेकिन गेंद पर बार बार लार लगाने की हालत में पांच रन की पेनल्टी लगेगी जो बल्लेबाजी कर रही टीम को मिलेंगे। इसके साथ ही गेंद को सैनिटाइज करने का भी नियम रखा गया है।

टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन क्वालिफिकेशन अवधि बढ़ी

कुआलालम्पुर, (एजेंसी)। विश्व बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए ही टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन क्वालिफिकेशन विंडो को 15 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं क्वालिफिकेशन अवधि पहले 25 अप्रैल को समाप्त होनी थी। बीडब्ल्यूएफ के मुताबिक सिंगापुर ओपन इवेंट क्वालिफिकेशन के लिए अंतिम टूनार्मेंट होगा और इसे भी एक से छह जून की नई तारीखों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा मलेशिया ओपन, जिसे शुरूआत में 31 मार्च से चार अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया था, को वापस 25 से 30 मई तक कर दिया गया है जबकि अप्रैल में निर्धारित मलेशिया मास्टर्स को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। बीडब्ल्यूएफ ने अपने एक बयान में कहा कि मलेशिया ओपन और सिंगापुर ओपन के लिए नई तारीखें निर्धारित करने के साथ-साथ बीडब्ल्यूएफ ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 और इंडोनेशिया ओपन 2021 के स्थगित होने की भी पुष्टि की है। नियत समय में इन टूनार्मेंटों के लिए प्रतिस्थापन तारीखों की घोषणा की जाएगी। बीडब्ल्यूएफ टोक्यो 2020 योग्यता प्रणाली को अपडेट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत आईओसी द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद अंतिम अद्यतन नियम साझा किए जाएंगे। ओलंपिक क्वालीफाइंग टूनार्मेंट की तैयारी जारी रहेगी, क्योंकि योनेक्स स्विस ओपन 2021 (दो से सात मार्च) और योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 (17 से 21 मार्च) के साथ अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन फिर से शुरू होने के लिए तैयार है।

यूईएफए यूरोपीय लीग मुकाबलों में टोटेनहम और वोल्फबर्जर के बीच मैच में गोल करने का प्रयास करते हुए अमेरिका के एलेक्स मोर्गन।

टीवी अंपायर के फैसले पर फिर उठा विवाद

अहमदाबाद, (एजेंसी)। भारत और इंग्लैंड के बीच यहां मोटेरा स्टेडियम में खेले जा रहे दिन-रात्रि के तीसरे टेस्ट मैच में एक बार फिर टीवी अंपायर के फैसले पर विवाद हुआ है। वहीं इससे पहले चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी टीवी अंपायर के कई फैसलों पर विवाद हुआ था।

भारतीय पारी के दूसरे ही ओवर में मैदानी अंपायर अनिल चौधरी ने शुभमन गिल को आउट दिया पर टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद फील्ड अंपायर के फैसले को पलट दिया। टीवी अंपायर सी शम्सुद्दीन ने एक ही फ्रेम को देखकर अपना निर्णय दे लिया हालांकि सॉफ्ट सिग्नल के नियम के अनुसार फील्ड अंपायर के निर्णय को पलटने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। टीवी अंपायर के फैसले के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट सहित सभी खिलाड़ियों ने नाराजगी व्यक्त जाहिर की।

भारतीय पारी के दूसरे ओवर में ब्रॉड की चौथी गेंद पर शुभमन का कैच स्लिप में स्टोक्स ने पकड़ा। अंपायर ने इसे आउट दिया क्योंकि वे पूरी तरस से तय नहीं थे कि स्टोक्स ने गेंद को सही से पकड़ा है या नहीं।

इसके बाद फील्ड अंपायर ने अंतिम निर्णय के लिए टीवी अंपायर का सहारा लिया।टीवी रिप्ले में साफ दिखा रहा था कि स्टोक्स ने जब गेंद पकड़ी थी जब उनके हाथ गेंद के नीचे नहीं थे पर नियम के अनुसार टीवी अंपायर को अलग-अलग एंगल से इसे देखना चाहिए था। पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने टीवी अंपायर के जल्द फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीवी अंपायर ने निर्णय देने में तेजी दिखाई हालांकि निर्णय सही था।

स्मिथ को इस बार दिल्ली कैपिटल्स के खिताब जीतने की उम्मीदें

नई दिल्ली, (संवाददाता)। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़कर उत्साहित हैं। स्मिथ को उम्मीद है कि उनकी टीम इस बार खिताब जीतने में सफल रहेगी। स्मिथ ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद स्मिथ ने उम्मीद जताई है कि वह आगामी सत्र में इस टीम को इंडियन प्रीमियर लीग (क्ढछ) में पहला खिताब दिलाने में सफल रहेंगे। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज कर दिया था। हाल की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2.2 करोड़ रुपये में खरीदा है। स्मिथ ने आईपीएल में 95 मैचों में 35.34 की औसत से 2333 रन बनाये हैं। इस बल्लेबाज ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैं वास्तव में इस साल टीम से जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं। टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी और शानदार कोच रिकी पोंटिंग है। मैं टीम से जुड़ने और उसके साथ कुछ सुखद यादें जोड़ने को लेकर उत्साहित हूं।उम्मीद है कि मैं टीम को पिछले साल की तुलना में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद करूंगा। स्मिथ के इस वीडियो पर वहीं पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच वसीम जाफर ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। जाफर ने शोएब अख्तर से जुड़ा एक मीम शेयर कर स्टीव स्मिथ की ट्रोलिंग की है। यह स्टार बल्लेबाज 2019 में राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा था और 2020 में यूएई में वह उसका कप्तान था।